(ii) G.S.R. No. 743(E), dated the 2nd September, 1987, publishing the Foreign Exchange Conservation (Travel) Tax Rules, 1987. [Placed in Library. *See* No. LT-4973/87 for (i) and (ii)].

I. Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Promotion) Rules, 1987.

II. Foreign Exchange Regulation (Amendment) Rules, 1987.

III. Date of enforcement of Chapter V of the Finance Act, 1987.

SHRI B. K. GADHVI: Sir, I also beg to lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification G.S.R. No. 824(E), dated the 25th September, 1987, publishing the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Promotion) Rules, 1987, under sub-section (3) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956. [Placed in Library. *See* No. LT-4970/87].

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification G.S.R. No. 847(E), dated the 9th October, 1987, publishing the Foreign Exchange Regulation (Amendment) Rules, 1987, under sub-section (3) of section 79 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973. [Placed in Library. *See* No. LT-4971/87].

III. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification G.S.R. No. 741(E), dated the 2nd September, 1987, appointing the 15th day of October, 1987 as the date on which Chapter V of the Finance Act, 1987, shall come into force. [Placed in Library. *See* No. LT-4972/87].

Notification of the Ministry of Commerce

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): Sir, I beg to lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Commerce Notification S.O. No. 922(E), dated the 15th October, 1987, amending Government Notification S.O. No. 281(E), dated the 1st April, 1987, so as to allow the import of Open General Licence items covered by Appendix 6, List—8, Part-I of Import and Export Policy, 1985—88 (Vol. I) by Export Houses/Trading Houses. [Placed in Library. See No. LT-4976/87].

STATUTORY RESOLUTION APPROVING THE CONTINUANCE IN FORCE OF THE PRESIDENT'S PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RESPECT OF PUNJAB—Contd.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल (पंजाब) : चेयरमैन साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे पंजाब की स्थिति के बारे में बोलने के लिये आज दुबारा चांस दिया ताकि मैं अपने विचार सदन में रख सकूं ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए]

महोदय, कल मैं यह कह रहा था कि पंथिक कमेटी जिसका अस्तित्व न जाने कहां से हुआ, न वह कोई इलेक्टेड बाडी है और न कोई नामीनेटेड बाडी है । दीवाली के दिन वहां पर सरबत खालसा के नाम से कोई इकट्ठा नहीं हुआ । वाइस चेयरमैन साहब, न हाउस आर्डर में है और न आपका ध्यान है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मेरा बिल्कुल ध्यान है । आप बोलिये ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : दीवाली के दिन अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के अन्दर न तो सरबत खालसा नाम की कोई चीज हुई और न कोई इकट्ठा हुआ लेकिन दो-चार लोगों ने अपने हाथ से लिखकर एक प्रेस नोट इश्यू कर दिया

[श्री हरेन्द्र सिंह हंपपाल]

और वह प्रेस नोट किसी पत्रकार को दे दिया। महोदय, अफसोस की बात तो यह है और मैं आपके माध्यम से प्रेस को भी यह कहना चाहूंगा, यह अपील करना चाहूंगा कि इतने इररिस्पांसबल नोट को जिसमें यह लिखा था कि सरबत खालसा हुआ, वहां पर ये ये रेज्योल्यूशन पास किये गये उसको इतनी पब्लिसिटी दी। जबकि सच्चाई यह है कि कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया लेकिन अगले दिन देश के तकरीबन सारे अखबारों ने इसको छापा। इससे बहुत बड़ा नुकसान देश का होता है। कोई इस तरह इन्सीडेन्ट हुआ ही नहीं या बहुत छोटी मात्रा में हुआ लेकिन आपने उसको इतना अधिक ब्लो-अप कर दिया जिससे सारी दुनिया को लगा कि शायद ऐसा ही हुआ है। यह मुनासिब बात नहीं है। प्रेस की भी कुछ रिस्पांसबिलेटी है, प्रेस को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पंथिक कमेटी का कोई अस्तित्व वहां पर नहीं है, पंथिक कमेटी कोई इलेक्टेड बाडी नहीं है। पंथिक कमेटी को किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया। इलेक्टेड बाडी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी है। वह चले या ना चले, वह एक बने या दो बने, यह उनकी मर्जी है कि कब वहां उमका चुनाव करायें। यह पंथिक कमेटी का ही अधिकार है कि वहां पर हेड प्रीस्ट को वह रखे निकाले या नया बनाए या हटाए। किसी पंथिक कमेटी के पास कोई लीगल अधिकार नहीं है कि वह ऐसा कर सके। पंथिक कमेटी का जो मुद्दा है जो ध्येय है वह सिर्फ इतना है कि वह देश का विभाजन करना चाहते हैं और हिंसा में विश्वास रखते हैं। ऐसी पंथिक कमेटी जो वहां पर एग्जिस्ट भी नहीं करती और अफसोस की बात है कि देश के बड़े बड़े लीडर वहां पर चले जाते हैं सुबह हवाई जहाज से वहां लैंड करते हैं शाम को हवाई जहाज से चले आते हैं और वहां से यह बयान देते हैं कि पंथिक कमेटी से सरकार को बात करनी चाहिये। यह बड़ी शर्मनाक बात है। जिस कमेटी का अस्तित्व न हो जिसके साथ कोई न हो जिसका ध्येय देशद्रोही हो उसके लिए देश के विपक्ष के बड़े-बड़े नेता वहां जा कर समर्थन कर दें तो हालात और बिगड़ जाते हैं। प्रेस को भी मैं दोबारा यह कहना चाहूंगा कि ऐसे गैर-जिम्मेदारी की कोई बात वो न उछालें जिससे लोगों के दिलों में भ्रम पैदा होता है। जो पंजाब की स्थिति इस वक्त वहां पर चल रही है पहले से बहुत बड़ी मात्रा में कंटेंड है। अगर हम ध्यान से देखें तो यह सही है अगर फिगर्ज देखें तो किलिंग्ज की फिगर्ज शायद इस पीरियड में ज्यादा हों बनिस्बत पहले पीरियड से लेकिन अगर उसको हम ध्यान से देखें तो यह किलिंग्ज, लूटिंग तथा आरसन जो इस वक्त वहां पर चल रही है वह एक रिट्रक्टेड एरिया में है कंटेंड इन ए कपल आफ डिस्ट्रिक्टस जब कि पहले यह सारे पंजाब में फैली हुई थी और यह किलिंग्ज इस प्रकार की हैं कि पहले वह लोग अपने खास मुद्दे पर जाकर बड़े बड़े लोगों को मारते थे लेकिन अब गिनती को बढ़ाने के लिए और अपनी एग्जिस्टेंस को मेनटेन करने के लिए उन्होंने यह काम शुरू कर दिया है कि किसी एक घर में गये छोटे बच्चे से लेकर कर बड़े बूढ़ों तक स्त्री पुरुष सब को मार दिया ताकि उनकी गिनती बढ़ जाए उन्होंने निहत्थे बेकसूर तथा बिलकुल छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा और इस तरह से वे अपनी किलिंग्ज की गिनती को बढ़ा रहे है। इसलिये मैं यह कहता हूं कि स्थिति पहले से कंट्रोल में है और रिस्ट्रिक्टेड विदिन ए कपल आफ डिस्ट्रिक्टस इन पंजाब और गिनती की बात जैसे मैंने कही वह गिनती इस तरह से बढ़ रही है। मैं यहां पर एक मिसाल यह देना चाहूंगा कि वहां पर पहले से सिचुएशन इम्प्रूव्ड है। एक तो जितनी दुकानें मीट, शराब या नाइयों को जो पहले बन्द करा दी गई थीं वह दोबारा पूरी तरह से स्वतन्त्रता से काम कर रही हैं और खुल गई हैं। पंजाब में अभी पेडडी क्राप हुई है। वहां पर स्थिति अच्छी होने की एक यह मिसाल है कि पंजाब भी उस रिजन में है जहां पर नार्मल वर्षा से 30 परसेंट कम वर्षा हुई है। जैसे कि गुजरात राजस्थान का रिजन है उसी रिजन में पंजाब आता है जहां पर नार्मल से 30 परसेंट कम वर्षा हुई है। इसके

बावजूद भी आज 35 लाख से 40 लाख टन पेड्डी पंजाब सेंट्रल पूल को दे रहा है। इतनी ही सारे हिन्दुस्तान में कुल मिला कर के होगी जितनी अकेला पजाब आज दे रहा है। मैं पंजाब के किसान को बधाई देना चाहूगा। यह नहीं कि वहां पर सूखा नहीं था वहां पर भयंकर सूखा था। सब-साइल वाटर 20–25 फुट नीचे चला गया था। वहा के किसान ने काश्तकार ने अपने गहने बेच कर अपनी दूसरी चीजों को बेच कर अपने ट्यूबवेल्ज को नीचे किया और ट्यूबवेल्ज के जरिये से सिंचाई कर के धान पैदा किया। यही नहीं, अगर जल्दी नहीं मिलो तो डीजल इंजन लगाकर उसको पैदा किया। पंजाब में इस साल इसी पीरियड से पिछले साल से 53 करोड़ रुपये का ज्यादा डीजल खर्च हुआ है, यह 53 करोड़ रुपया सिर्फ पंजाब के किसानों ने पे किया है इसीलिए वहां के गवर्नर साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल रिक्वेस्ट करके 17 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिलवाया है। यह बोनस कोई तोहफा या गिफ्ट नहीं है पंजाब के किसान के लिए, लेकिन जो उन्होंने मेहनत करके पैसा खर्च किया है वह रुपया दिलवाया गया है। मेरा कहना है कि इस वक्त पंजाब के गवर्नर श्री सिद्धार्थ शंकर रे और वहां के पुलिस चीफ रिबेरो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको इस काम में अगर हम सहायता न कर सकते हों तो कम से कम लगातार उनको यह काम कंटीन्यू करते रहने देना चाहिए ताकि अगले 6 महीनों के अन्दर जो पंजाब के अंदर स्थिति में इम्प्रूवमेंट हुआ है वे उसको और कंटीन्यू कर सकें। मैं यह भी चाहूंगा कि पंजाब के अन्दर बहुत जल्दी पापुलर रूल लागू किया जाये। पापुलर रूल तभी वहां पर चल सकेगा .... (**व्यवधान**) पंजाब में आज स्थिति है कि न वहां पर कांग्रेस की सरकार चल सकती है न अकाली दल बरनाला की चल सकती है, न वहां पर अकाली दल बादल या किसी और ग्रुप की चल सकती है। इसलिए प्रेजेंट स्थिति को वहां पर चलने देना चाहिए कि मिचुएशन और ज्यादा कंट्रोल में कर सकें।

मैं एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। यह बार-बार कहा गया है कि जोधपुर के डिटेन्यूज को छोड़ना चाहिए। यह बिल्कुल सही है कि जिनका कसूर कम है उनको रिव्यू किया जाये और जल्दी छोड़ा जाये लेकिन इसके साथ-साथ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि बरनाला साहब की सिर्फ एक गलती से उनको वहां के राज से हाथ धोना पड़ा। जब वे वहां के चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने बगैर सोचे समझे जितने लोग पकड़े गये थे सबको छोड़ दिया। उनको छोड़ने से पंजाब की स्थिति दुबारा बिगड़ गयी और वे उसको संभाल नहीं पाये। डिटेन्यूज को जरूर छोड़ना चाहिए लेकिन पंजाब की स्थिति को सुधारने के बाद, पहले पंजाब की स्थिति को सुधारने के लिए जो प्रेजीडेंट रूल है इसको कंटीन्यू करना चाहिए।

फाल्स इन्काउंटर्स की बात कही गयी। उसमें मिस्टर रिबेरो और गवर्नर आफ पंजाब ने बार-बार यह बात कही कि अगर एक भी केस उनके सामने ऐसा लाया जाये, पब्लिक मीटिंग्स में उन्होंने अनाउंस किया कि एक भी केस ऐसा लाया जायेगा जिससे यह महसूस हो कि कोई इनोसेंट आदमी मारा गया है तो वे उसकी इन्क्वायरी कराएं और आज तक एक भी केस उनके सामने ऐसा नहीं लाया गया है। यह उनके थ्रू मेरी जानकारी है। गवर्नर साहब का यह कहना है कि जितने लोग इन्काउंटर्स में मारे गये है ... (**व्यवधान**) उनमें से एक भी आदमी ऐसा मारा गया हो जिसने 5 कत्ल से कम किये हों तो वह उनकी नोटिस में लाया जाये। कहने का भाव यह है कि जितने लोग वहां पर मारे जा रहे हैं जिनको हम एक्स्ट्रीमिस्ट, टेरोरिस्ट कहते हैं उनमें से एक-एक आदमी ने कम से कम 5 मर्डर किये हैं। कोई ऐसी बात न की जाये जिससे कि वहां की पुलिस का पैरा मिलिटरी फोर्सेज का वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का डिमारेलाइजेशन हो, जिससे वे अपना काम जिस स्पीड से जिस ढंग से कर रहे हैं वे न कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shri Gurupadaswamy. Now, I request the Members that they should not exceed the time limit given to them because we have to conclude this before 1.30.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): I will be taking my full time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I do not say you should not take your time. (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Then we can consider whether we should skip the lunch hour.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Karnataka): We can skip the lunch hours, Sir, because the debate is important.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): When the request was made yesterday that the House should adjourn and the debate should resume today, I said, "Yes, I have no objection", on the condition that we will take it up immediately after the Question Hour and there will be a time limit imposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That is because the P.M.'s statement was there and the Home Minister's statement was also there. If the House proceeds even skipping the lunch, we shall complete before 2.30.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I may then be allowed to reply at 1.15 p.m. Otherwise, I will be able to come back and reply about 2.30 p.m. I will have to be away for about half an hour. I will come back and reply. I can come back at 2.15 or so.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: You can listen to the Members.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): If you want more time for discussion, then you have to skip the lunch hour.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Yes, we will skip the lunch hour. If he has got any engagement, he can attend to that. Mr. Vice-Chairman, Sir, yesterday when my friend Shri Chidambaram made a reference to the report of the Governor, some of us said that the report was necessary to have a meaningful discussion in the House. It is unnecessary to take shelter under the Rules of Procedure. It is common sense that whenever a document is mentioned that document should be made available to the Members of the House. The purpose is to have a good and effective debate. Only in that context we suggested that. Therefore, my friend need not take refuge under the Rules of Procedure in this matter. Sir, it looks to me, having seen the effort on the part of the Constitution contemplates certain rule in Punjab, that President's rule, in the last six months, has failed. Sir, the Constitution contemplates certain contingencies where President's rule is required and the Constitution has limited President's rule to six months. Of course, it has given the power to extend it in extraordinary circumstances. Here is a case where there is an admission and confession on the part of the Government that President's rule has failed in the first six months and they hope to succeed, according to him they hope to succeed, in the next six months. I do not know whether this hope against hope will succeed at all. I wish he succeeds. All the best for him if he is going to succeed. My fears are even in the next period of six months he may not succeed. It has been claimed by the Government that whatever the method they have adopted during the first six months, it has yielded results. I am amused to know this kind of remark, this opinion. If I may be permitted with little diversion, I think Mr. Rajiv Gandhi made two mistakes. The first mistake was, he appointed Mr. Buta Singh as a Minister in the Government

of India. The second mistake was, he made him the Home Minister. I think Mr. Buta Singh as Home Minister has nearly perfected the art of ineptitude and mismanagement of Punjab issue for which he deserves a national prize. He does not see what is happening; he does not see the facts, the realities. According to the statement of my friend, killings are going on non-stop, either way, killings by the terrorists, killings by the police and the para military forces; they have been escaping. We are made to believe, that they are only killings of the terrorists Is it so? Nearly 900 people have been killed during President's rule. My friends were waxing eloquent, all these 900 people were terrorists. Were they so? Was there no innocent people involved in the killings? Five thousand young men have been arrested so far, according to the figures I have Are all these 5000 men terrorists? I want to know. Are all of them suspects? There are more than 300 people in Jodhpur jail since a long time. Are they all terrorists or anti-social elements? If they are, why are they not tried? May I know whether Badal is a terrorist, Tohra is a terrorist? Where you class them? How do you categorise them? Where do you put them? Why are they not tried? There are Acts at your disposal. Bloodshed is going on in the streets of Punjab everyday and there is no let or hinderance to the various elements operating there. The situation is simply chaotic under the President's rule. Still my friend says President's rule is a boon, there has been containment of terrorism in Punjab, they are on the run, to use their words. They are on the run! Where are they on the run? Where are they going? 'On the run' means where? They are in Haryana perhaps, they are in Delhi, and they go back. My friends were saying that they are using more sophisticated weapons now than before and that money is flowing from outside sources. But there is no check or hinderance to that flow. If I have to believe their own figures, their own facts, then you have to permit me to say that the situation in Punjab is fast deteriorating and not improving at all. What are the facts which show improvement, if at all there is any, Sir? How does he say that there is improvement? There is more killing, there is more bloodshed and there is more insecurity. There are more robberies. Then how is it improving? I want to understand that. All their facts go against their own thinking and they suffer from an illusion, a dangerous illusion, that things are improving while they are not improving at all. If they are improving, I will be very happy. But they try to criticise people unnecessarily out of context, for no reason at all. Sir, here is Mr. Rajiv Gandhi trying to solve the ethnic problem in Sri Lanka through political means. But the same logic does not hold good in Punjab. It is a part of our own territory and no political solution is considered till terrorism is curbed. But he forgets, his colleagues have forgotten that terorism has risen out of political unsettlement. I am not holding any brief for anybody there. I am looking at the whole situation as a common citizen of India, as an ordinary citizen of India. Where are we going? Are we going towards any settlement or are we going towards unsettlement and towards instability for a long time to come? The basic things are forgotten. I am not for Khalistan and we all oppose Khalistan. No citizen of India, no patriot of India would subscribe to this theory. The overwhelming majority of people in Punjab are against Khalistan. But no effort has been made to look into the other aspect, the political aspect.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please conclude now.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I will take a little longer time now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You have already taken thirteen minutes.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I know. I am taking a little longer time because of the change: I know we are skipping the lunch hour.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): But there are ten more Members and I have to accommodate them.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I will be brief. You are very considerate, indeed.

Sir, my point is that the basic question is political and not law and order. We are missing this and we are taking a false step. Mr. Rajiv Gondhi said yesterday: "Unless the LTTE is agreeable to implement the accord, there is no question of withdrawal of the army or the fight.". Right. Then why is it not applied here? There was an accord and he is trying to save that accord in Sri Lanka. But he does not want to save his accord in Punjab. What has gone wrong with him, with his Government? By implementing the accord, by reaching a political settlement in Punjab, you will only be isolating the terrorists, the extremists. But this is conveniently forgotten. But you have given fodder to these terrorists to operate and the fodder is that the Government of India is not sincere and, therefore, they say that they are fighting for their cause. You are helping them. You are the abettor. Unconsciously you are the abettor of terrorism. The Government of India is an accomplice and abettor of terrorism in Punjab. You are playing a dirty role. The Home Ministry is simply wooden, inept, suffering from wrong perception and wrong approach in settling the problem of Punjab. It has been there for years. How long do you want us, to live with this problem, with this hell? I want to know. All things have been gone into in the past. We are opposing this extension. One of the needs of the hour is to have popular rule. I do not want to go into that question whether Barnala was right or wrong President's rule has failed. If popular rule has failed, you have failed more. You cannot succeed in this. Therefore, I demand two things. First, immediate political settlement. Second, restoration of poular rule. It may be a rule by Barnala or it may be a rule by somebody else. The very fact that you have kept the Assembly in suspended animation means that you want to resurrect it sometime. You want popular rule sometime. Why not now? If I may give my personal view, if one group cannot form a popular Government, why not Congress with others? I have no objection. I want popular rule. Let there be an all-party rule, all-party Government. In the last six months have you not even set up at least a consultative committee of MLAs, Why? I do not know. If you have, I stand corrected.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): Of MPs they have set up.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: MPs now. The first priority should have been an advisory committee or a consultative committee of MLAs there. You have not involved them. You do not want to involve them. You do not want to face them. That is your trouble. Why don't you even now set up a consultative committee of MLAs drawn from various political parties there? Therefore, Sir, I am sorry that the Punjab question has become more complicated. The policy of the Government of India towards Punjab has miserably failed. The strategy, the approach, the methods that are employed by the Home Ministry are nothing but wooden, inflexible. It lacks vision. It lacks statesmanship. Therefore, I have no doubt that the President's rule in the next six months will also fail. I am perfectly certain about it.

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I will not take much time because I know the constdaints undre which the hon. Minister is working. There are certain unpalatable things which I want to state. I have kept quiet on the issue of Punjab for a long time now. The last time I spoke on Punjab was at the time when the Akal Takht was being constructed. At that point of time I had spoken at length and given my views. I have kept quiet since then and have been watching developments. I wish the hon. Minister had tabled the Report of the Governor. I told him privately. And I agree that there is no real constitutional provision for it. But it would have been better for us and we would have known what the real compelling circumstances are at the moment. I know the constraints under which the Government is functioning. I know what

kind of problems are there in Punjab with terrorism and with the Government trying to make efforts to stamp it out. What is the root of this terrorism? My friend, Mr. Sukul, yesterday correctly pinpointed the root of this problem. There is always some kind of injustice which has taken place, which gives rise to a sense of desperation, and it is from that, that terrorism springs. And the hon. Member has very correctly said that it was the killings which took place during the regime of the Janata at the Centre, during the regime of Mr. Badal in Punjab on Vaisakhi Day of 1978 when 13 Sikhs were killed. That was the start of terrorism because it was from that killing what is started is a sense of injustice. It is from there. And that was not our creation. That was the creation of the Janata.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Why don't you solve it?

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH: If the hon Member will permit me.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You go on. You may not respond to it.

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH: I am afraid, I don't want to get into a debate. But I do want the hon. Members to hear me out because I have spoken after a long time and I do not speak very often. But when I do speak, please hear me. This is not just what I have to say. There are plenty of other things.. Who is saying that I am speaking nonsense?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You go ahead. You please look at me and speak.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Only the later part I heard. I was out.

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH: The Professor is my old friend. He is allowed to say what he likes.

Sir, the root cause was there. And it is only after that when the State starts suppressing the illegal acts that suppression by itself creates a further movement. That further movement has in-built within its further State repression which causes a further movement. It becomes a spiral. And this becomes a never-ending spiral. It is a fact that no terrorist movement has ever succeeded in the world. It is also a fact that whenever the Governments have tried to put down terrorism, they have had lots of problems. But, who are the fathers of this terrorism, this terrorism which we see today? Who are the fathers of it? When we talk amongst ourselves, we say we know it, that it is the foreign powers which are interfering in Punjab. I know for a fact that there are training camps in Pakistan. I know that arms are coming from other countries. I know money is coming from other countries. Today in the newspapers I read that in Amritsar we have caught one gentleman called Balkar Singh from the World Sikh Orgainsation. He brought money from Canada and from America. He brought money to distribute to various people for the purpose of terrorism. We have captured the man. We know from where this money is coming, we know who is trying to nurture it. But the point is that no plant can be watered unless the seedling is already there. The seedling is already there, the root is there. It is that root which is being watered by our foreign friends, who are trying to create trouble in this country. If the plant was not there, if the seedling was not there, if the root was not there, they could not interfere. And who are the fathers of this? I blame the Akali Party. And I say with responsibility that it is the Akali Party which is responsible, every single one of them. Who are the fathers of this terrorism? (*Interruptions*) Don't interrupt me now. My friend, hon. Gurupadaswamy was just saying: Is Tohra a terrorist, is Badal a terrorist? And I say, yes, they are terrorists. I will tell you why. (*Interruptions*) I will tell you why if you listen to me. Every single Akali politician today. I say, is a terrorist. (*Interruptions*). I say they are all terrorists. I will tell you why. Just wait a minute. Hear me out.

AN HON. MEMBER: If he is a terrorist, then you are also a terrorist.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Gurupadaswamy, that is his view.

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH: We are all terrorists. Every single one of them is a terrorist. I can even go to the extent of saying that every single Akali politician, when he is out of power, the first thing that he does is to give all kinds of extremist calls. They give slogans.

AN HON. MEMBER: Is Buta Singh also an extremist?

SHRI VISHVJIT PRITHIVIJIT SINGH: The Sikhs say, he is not even a Sikh.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Sir, he says that every Akali politician is a terrorist. This is a very grave charge.

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH: I say it with responsibility The Hon. Member, Mr. Upendra, is asking me a question. I say it with responsibility. Let me tell you that every single one, I have seen Mr. Badal and Mr. Barnala, the same Mr. Barnala, who is today accepted as a moderate, I have seen them both sitting in the Gurdwara here giving a call to the Army to revolt, calling upon the Sikhs in the Army to leave the Army. I have seen Mr. Badal doing this. I have seen Mr. Barnala doing it. I have seen Maharaja Amrinder Singh, who is a friend of mine, sitting on the dais with all kinds of terrorists, giving all kinds of calls, once he was not in power. I have seen every single one of the Akalis, the moment they are out of power, they give all kinds of extremist slogans. The youth of the State unfortunately gets excited by these calls which are given by irresponsible politicians when they are not in power. The moment these politicians come to power, they want that everything should become calm and quiet. Unfortunately, the youth once it is excited, it cannot easily be calmed down. Blood is hot. We are a warm blooded nation and that very youth gets excited and then that breeds terrorism. I say that the fathers of this nation are our irresponsible politicians. We ourselves are responsible for this terrorism, we politicians. (*Interruptions*) . I tell you Professor, if you will just keep quiet. Why do you want to interrupt me?

AN HON. MEMBER: May I ask a question?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Are you yielding?

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH: No. I am taking my glass of water, I am not yielding.

And, Sir, this problem occurs when power becomes the final arbiter. It is power which is the arbiter. The moment they are in power, they become moderates. The moment they are out of power, they become extremists. This is the problem which we are facing today. Terrorism, as I have said before, cannot in the final analysis solve any problems. It cannot succeed. We have seen movements in the world which have been carried on for 100 years, 200 years, 500 years. They have not succeeded. On the other hand, I would urge upon the Hon. Minister that State repression also cannot succeed. If we want that merely by force of arms we can solve a problem we cannot solve it. I do agree with my friend, Shri Gurupadaswamy, when he said just now that only a political solution can succeed. It is a fact and we have ourselves accepted it that it is only a political solution which can succeed in solving the whole thing. But what can this political solution be? Today the opposition is asking for a popular Government to be installed. Everybody is asking for a popular Government to be installed. Which popular Government, I would like to ask, whom do you want to instal?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY. The Congress.

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH: Do you want Mr. Badal? Do you want Mr. Tohra? Do you want Mr. Barnala? Do you want Mr. Amrinder Singh? Whom do you want, because each one of them does not want any of the others?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Send Buta Singh.

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH: Shri Buta Singh is not an MLA, and in any case he is from Rajasthan.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Send him for six months.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The time is limited. Please do not interrupt.

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH: If the opposition wants to take my time, what can I do?

The point, Mr. Vice-Chairman, is this, which Government can be formed there? They are asking for a popular Government. There is no popular Government which can be formed. Each one of them is fighting with the other. There is total disunity. And let me tell you. The SGPC elections which took place just now are the proof of the pudding. They show how there is a total disunity amongst the Akali camps. There is no one person whom we can pick up and say yes, you can form the government. Even the last government was there because we supported it. This is a problem.

Now a very unpopular thing I am going to say. There are people who do emerge. It is not that people do not emerge in Punjab who are capable of a political solution, who are capable of causing a political solution. There are people with the stature to be able to do it. Let me tell you about our problem today. One problem, a major problem, we face in this country is—as the hon. Prime Minister mentioned when he was in the United States, and as often said by us from this side and by the Members of the Opposition—the fact that our perceptions have become clouded. Our perceptions have become so narrow-minded that we think only in terms of black or white. We do not think in terms of shades of grey. Once we make up our mind that a particular policy or a particular individual is to be tainted black, black he or it shall remain for ever regardless whatever the proof that might be forthcoming. We decided in our wisdom, the press decided in their wisdom that Ragi Darshan Singh, when he emerged on the scene, was an extremist and he was carved with the brush and it was said that Ragi Darshan Singh had become as such, in the media and it clouded our perception. We all thought that the Ragi was another Bhindranwale who had come up. We thought that. But today, the Ragi has proved himself. He kept proving himself all along. He kept taking a nationalist posture. He kept trying to say that he was for the unity of this country, that he was for the Constitution of this country. But none of us took him seriously. He has finally gone to the extent of taking open fight with the militants. Today there is no way to talk to him because he has become irrelevant. Time is not there; we cannot talk to Ragi and even if we talk to him, he is totally irrelevant today; he does not matter today. But let me tell you that individuals are bound to emerge as the time goes on. Somebody does emerge out of the State of Punjab, somebody who is capable of yielding the youth and everybody together. I would urge upon the hon. Minister that we must, at that point of time, find a political solution. Let us not lose that opportunity.

I take this opportunity to lament all the deaths taking place or that have taken place in Punjab. Everybody, whether it be an innocent bystander, or whether it be a politician, whether it be a policeman, whether it be an army man, whether it be a

[Shri Vishvjit Prithvijit Singh]

terrorist, is related to somebody. The death affects a father, affects a mother, affects a brother, affects a son, affects a wife, affects the whole family. We are one family of Indians. We ought to be concerned about the deaths that are taking place in Punjab.

I urge upon the hon. Minister that now that we are giving another six months' extension to President's Rule, before these six months are up, I hope and pray to God that we find a solution to this problem and that we do not have to extend this rule any farther than this. Thank you.

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Ten minutes.

श्री प्रमोद महाजन : मुझे आप उतना ही समय दीजिए जितना आपने और पार्टियों के सदस्यों को दिया। और पार्टियों को आपने जिस अनुपात में समय दिया उसी अनुपात में मुझे भी दीजिये, उससे एक सैकिंड ज्यादा मत दीजिये।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस परिप्रेक्ष्य संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय, किसी भी समस्या का समाधान निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। इस सिद्धान्त से पूर्ण रूप से सहमत होने के पश्चात् भी मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। हमारी धारणा में पंजाब सम्बन्धी केन्द्र सरकार की नीति घुमुल है, दिशाहीन है, गलत है फिर भी मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग सबसे पहले हमने की थी। जब केन्द्र सरकार बरनाला जी की सरकार पर प्रशासन के सुधार बिठेर रही थी केन्द्र सरकार बरनाला जी की सरकार को रणजीत सिंह की सरकार के बाद में बढ़िया सरकार मान रही थी तभी हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। आखिर क्यों ? हमने जब राष्ट्रपति शासन की मांग की थी तब अकाली सरकार आपसी झगड़ों के कारण विधान सभा में अपना बहुमत खो चुकी थी। अकाली सरकार कांग्रेस की बैसाखियों के आधार पर खड़ी थी। उस सरकार में कुछ ऐसे तत्व थे जो उग्रवादियों से सहानुभूति रखते थे समन्वय रखते थे सहकार रखते थे और पंजाब के इस्थिति के बारे में अकाली और केन्द्र सरकार दोनों एक दूसरे की ओर अंगुली उठा कर अपने आप को दोषमुक्त करते थे और इसलिए हमारी धारणा में में एक ओर पंजाब की जनता को राहत की सांस मिले और दूसरी ओर पंजाब की स्थिति की सीधे जिम्मेदारी किसी न किसी पर हो कोई न कोई देश को इस स्थिति के बारे में अपने आप को जिम्मेदार माने इसलिए हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। दुर्भाग्य से आज तक इस स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया। पंजाब में आज कोई जनप्रिय सरकार बनाकर समस्या का समाधान ढूंढ लेगा ऐसा अगर हम में से किसी को लगता हो तो मुझे क्षमा कीजिये हम हम बड़े भ्रम की दुनियां में रह रहे हैं। आज पंजाब में कोई एक दल जनप्रिय सरकार बना कर पंजाब की समस्या का समाधान ढूंढ नहीं सकता। हां, शायद एक रास्ता हो सकता है जो अभी अभी हमारे मित्र गुरुपदस्वामी जी ने कहा है वह उनकी व्यक्तिगत राय थी। मैं एक ऐसी पार्टी से आता हूं जहां व्यक्तिगत और पार्टी की राय में अन्तर रखने की अनुमति कम से कम होती है इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से कह सकता हूं कि पंजाब की स्थिति असाधारण है इसका उत्तर भी अगर असाधारण ढूंढना होगा तो क्या सरकार इस बात की सम्भावना का पता लगाने का प्रयास करेगी कि पंजाब में कोई सर्वदलीय सरकार बन सकती है। यह प्रयोग अनोखा होगा अद्भुत होगा अपने आप में कठिनाइयों से और समस्याओं से भरा होगा, विरोधा होगा लेकिन गत 7 वर्षों में हमने इतने प्रयोग कर के देखे हैं तो क्या सर्वदलीय सरकार जिसमें

सभी आस्थाओं और सभी विचारों का समन्वय हो और अपने आप को एक मान कर पंजाब की समस्या सुलझाने का प्रयास करने वाली सरकार इस रूप में वह मुखर आए तो यह एक ऐतिहासिक प्रयोग होगा लेकिन इतिहास में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका उत्तर ढूंढते समय हम को इतिहास के पहले पृष्ठ पर कुछ लिखा पाया नहीं जाता हमें अपना इतिहास अपने आप बनाना पड़ता है और इसलिए सरकार इस सूचना पर गम्भीरता से विचार करे, यह मेरी प्रार्थना होगी। यद्यपि हम इस संकल्प का समर्थन करते हैं लेकिन हम यह नहीं मानते कि राष्ट्रपति शासन पंजाब समस्या का समाधान है। यह अवस्था तो केवल 6 महीने की है। 6 महीने के बाद डर यह लगता है कि केन्द्र सरकार ने जिस अकर्मण्यता के साथ अपने गय 6 मास बिता दिये उसी प्रकार अगर आने वाले 6 मास उसी अकर्मण्यता से केन्द्र सरकार, हम सभी राजनैतिक दल और हमारा समाज बिता दे तो 6 महीने के बाद हम उसी स्थिति में पहुंच जायेंगे जिसकी कल्पना करना सबके लिए मुश्किल होगा। इसलिए इस 6 मास का प्रयोग इसके समाधान की दिशा में जाने के लिए प्रयासों का प्रयोग होना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि उग्रवादियों का कड़ा मुकाबला होना चाहिए। पंजाब का उग्रवाद दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक उग्रवाद है। दुनिया के इतिहास में उग्रवादियों ने आज तक एक वर्ष में जितनी हत्याएं की है उससे कई गुना ज्यादा हत्याएं पंजाब के उग्रवादी एक मास में करते हैं। भारत की जनता इस अनोखे उग्रवाद का सामना कर रही है और इस उग्रवाद को अनुनय से उत्तर नहीं मिलेगा। हमने अनुनय का एक प्रयोग आजादी के पहले करके देखा और हमने पाकिस्तान के रूप में अपने देश का विभाजन देखा। कुछ प्रश्नों का अनुनय से कभी उत्तर नहीं मिलता है।

मैं सभी सिखों को देशद्रोही नहीं मानता, सभी अकालियों को उग्रवादी नहीं मानता। कभी कभी मुझे लगता है कि सिखों से देशभक्ति का प्रमाणपत्र मांगना मानों सूरज से रोशनी की गारन्टी मांगने के समान है। सिखों के प्रति इतने आदर और इतने एकत्व की भावना होने के बाद भी जहां तक उग्रवादियों का प्रश्न है उनको केवल सिरफिरे नवयुवक कहकर अनुनय से इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा और इसलिए इसका कड़ाई से मुकाबला करने में सरकार को हिचकिचाना नहीं चाहिए।

सभी कहते हैं कि उग्रवादियों को पाकिस्तान से मदद मिलती है। हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री ने लन्दन में एक टेलिविजन इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान बारबार हमें आश्वस्त करता है कि मदद नहीं करेंगे लेकिन इन ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट। कभी कभी तो प्रधान मंत्री जी की और उनकी सरकार की, कि पाकिस्तान मदद करता है, यह बात सुनकर हमें अपने आप पर अपने देश पर घृणा आती है कि कितनी बार हम कहेंगे कि पाकिस्तान मदद करता है। आखिर पाकिस्तान हमारा थोड़ा सा मित्र और पुरातन उससे अधिक मित्र रहा है, इसलिए यह पाकिस्तान की करतूत नयी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से उग्रवादियों को जिस प्रकार सहायता होती उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं। अगर हमारे घर में चोर घुस आय तो पहले कमरे से दूसरे कमरे में जाकर बीबी से कहें कि देखो पाकिस्तान का चोर अंदर घुस आया है जरा हम पीछे और चल जाये।

हम एक शिकायत करते हैं, प्रधान मंत्री जी से एक ही शिकायत करते हैं कि पहले भी राज्य सभा ने आपको सुरक्षा पट्टी का अधिकार दिया था लेकिन इस सुरक्षा पट्टी का गर्भपात क्यों हुआ। अधिकार आपने मांगा था उसके बाद आपको मई से अगस्त तक समय था जिसमें आप अपने आप कर सकते थे बरनाला जी को रोकने के लिए नहीं थे। लेकिन आपने सुरक्षा पट्टी बनाई नहीं वह सुरक्षा पट्टी केवल पंजाब के लिए नहीं थी यह काश्मीर से लेकर कच्छ तक थी क्योंकि पाकिस्तान हमारी सीमाओं पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी

[श्री प्रमोद महाजन]

करता रहा है। इसीलिए सरकार ने स्वयं सुरक्षा पट्टी की मांग की थी। हम आखिर अपनी मांग से क्यों मुकर गये। मैं इस विषय को लम्बा नहीं खींचना चाहता हूं लेकिन मैं फिर मांग कर रहा हूं कि इस सुरक्षा पट्टी के बारे में सरकार को दो टूक निर्णय लेना चाहिए इसमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन उग्रवादियों का निर्मूलन इस समस्या का आधा हिस्सा है। हम सभी जानते हैं कि नवम्बर, 1984 में दिल्ली में दंगे हुए थे। इंदिरा जी की हत्या हुई। इंदिराजी की हत्या अपने आप में एक जघन्य अपराध था। हत्या करने वाला सिख था। दुर्भाग्य से हमारे देश में किसी भी नेता की हत्या करने वाला हो, करने वाला किसी न किसी धर्म का होता ही है बिना धर्म के हम इस देश में जन्म नहीं ले पाते हैं। लकिन
1.00 P.M. इन्दिरा जी की जघन्य अपराध, हत्या का हत्यारा सिख था, इसलिए हमको यह अधिकार नहीं मिलता कि दिल्ली में किसी सिख बहिन की गोद से उसका छह महीने का लड़का उठा कर उसी के पति के जलते ट्रक में फक देंवे।

इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ में 70 करोड़ की आबादी के इस देश की राजधानी में हजारों... (व्यवधान)

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : आग में तेल डाल रहे हैं आप। ... (व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : जिस बात को आप समझते नहीं हैं, उस पर न बोलें तो अच्छा होगा।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं।... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : वह तो जो घटना हुई, उसको बता रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : मैं यह कह रहा हूं कि अढ़ाई साल तक, सिखों की हत्या होने के बाद एक भी व्यक्ति को सजा—मैं विठ्ठलराव जी की बात स्वीकार करता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर कोई उंगली उठाना चाहते हैं, तो उसको रामलीला मदान में फांसी दी जए, लकिन आप सज्जन कुमार की बात कीजिए।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : आप पूरी कांग्रस पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर भी ऐसा इलजाम नहीं लगा सकते। आपकी केवल इजलाम लगाने की आदत है।

श्री प्रमोद महाजन : मैं सज्जन कुमार का नाम ले रहा हूं।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : आपकी पार्टी की करतूत तो हमें बहुत मालूम हैं। आप एसे मत कहिए कि आप बहुत साफ हैं। ...(व्यवधान) पूरे देश में हलचल मचने वाल आप ही लोग हैं।...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The debate has been going on at a very high level. Please maintain it.

श्री प्रमोद महाजन : इसलिए इन हत्यारों को सजा दिये बिना, वह किसी भी दल के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संस्था के हों, इस प्रश्न पर मैंने पहले भी यह कहा था।

श्री विठ्ठलराव जी आप अपने आप आइने में देख रहे हैं। मैंने नाम तो लिया ही नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : नहीं, नाम नहीं लिया है।

श्री प्रमोद महाजन : अगर ऐसे दोस्त आपके पास हों, तो आपको दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : चेहरे बदल जाते हैं, यह मत भूलिए।

श्री प्रमोद महाजन : मैंने यही कहा कि जाधव जैसे दोस्त आपकी पार्टी में हों, तो आपको दुश्मनों की आवश्यकता ही नहीं है।

मैं दूसरी चीज इसमें यह जोड़ना चाहता हूं कि जो प्रकाश सिंह बादल जी को बन्दी बना कर रखा है... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please conclude now, because there are still eight more speakers.

श्री प्रमोद महाजन : आई एग्री, लेकिन, जो बीच में बोलते हैं, वह समय तो आप काटते नहीं हैं।

मुझे लगता है कि यदि प्रकाश सिंह बादल पर कोई आरोप है, तो उनको खुली अदालत में लाइये और अगर नहीं तो उन्हें बन्दी बनाये रखने से पंजाब की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मुझे कभी-कभी शर्म आती है कि इतना ही नहीं, उनके घर वाले अगर उनको जेल में रहते समय एक टी०वी० का सेट देने की कोशिश करें, तो सरकार उस पर भी पाबन्दी लगाती है।

वैसे तो दूरदर्शन पर आपका इतना अधिकार है कि प्रकाश सिंह बादल ने पता नहीं क्यों मंगवाया है, वह देखते-देखते इतने बोर हो जायेंगे कि वह लगायेंगे ही नहीं, वापिस भेज देंगे। लेकिन फिर भी आपने उन्हें टी०वी० सेट भेजने से इंकार किया।

जो मैंने प्रश्न पूछा था कि जोधपुर के बंदियों की स्क्रीनिंग करने वाले हैं, सरकार कहती है कि यह हमारे विचाराधीन हैं। अढ़ाई साल से विचाराधीन हैं और प्रधान मंत्री कहते हैं कि मेरी सरकार बहुत तेजी से काम करती है। साढ़े तीन साल हो गये और यह विचाराधीन है। यह विचारना आपके अधीन है या पराधीन है? आप कितने समय तक विचार करेंगे? क्या जोधपुर में जितने भी बंदी बनाये हैं, उसमें कितनी महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं, इनकी संख्या कितनी है?

यह जो बंदी बनाये गये हैं, उनमें अगर कुछ निर्दोष लोग हैं, तो उनको क्यों छोड़ा नहीं जा सकता? अगर आपके पास कुछ सबूत हैं, तो उनको अदालत में लायें क्यों नहीं लाया जा सकता? हो सकता है कि मुट्ठी भर ऐसे हों कि जिनको आप अदालत में नहीं ला सकते, लेकिन आपको शक है। कुछ तो कठिनाइयां हम समझ सकते हैं, लेकिन बेगुनाहों को इस प्रकार से रखने से समस्या का समाधान नहीं होगा और इसलिए अंत में केवल मुझे इतना कहना है कि उग्रवाद का कड़ाई से निर्मूलन, सुरक्षा पट्टी का निर्माण, नवम्बर, 1984 के दंगे के गुनाहगारों को सजा, जोधपुर में बंदियों के निरापराधों की रिहाई, प्रकाश सिंह बादल जैसे नेताओं की रिहाई, इस रास्ते से हम चलें।

अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सभी कहते हैं कि पंजाब की समस्या का समाधान राजनीतिक है, यह सत्य है, लेकिन क्या राजनीतिक समाधान का अर्थ आनंदपुर साहब प्रस्ताव स्वीकार करना है? क्या राजनीतिक समाधान का अर्थ देश की एकात्मता, अखंडता और संविधान को चुनौती देने वालों से बात-चीत करना है? क्या राजनीतिक समाधान का अर्थ पंजाब गुंडाओं को राजनीति का अड्डा बनाने की अनुमति देना है? अगर इसका अर्थ कोई राजनीतिक समाधान लगता है तो यह राजनीतिक जले ही होगा लेकिन राष्ट्रीय नहीं है, यह अराष्ट्रीय समाधान होगा और इसलिए मुझे लगता है कि समय आया है पंजाब की समस्या का हम नहीं मानते कि कोई बना बनाय समाधान है, कोई तत्काल उपाय है। There are no ready-made solutions, there are no instant remedies. एक दीर्घकालीन नीति सरकार को, जनता को, सभी दलों को बनानी पड़ेगी व्यक्तिगत दलगत और धर्मगत स्वार्थ से ऊपर उठकर हम ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाकर अगर इस

[श्री प्रमोद महाजन]

प्रश्न था, इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि इस 6 महीने में कुछ उत्तर मिले अन्यथा डर यह लगता है कि,

"तारीखों ने ऐसे भी दौर देखे हैं जहां लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है।"

कहीं ऐसा न हो कि सदियों की सजा पाने की स्थिति हम पर आ जाए ?

धन्यवाद ।

श्री शरद यादव (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब के सवाल पर अपने वक्त के अनुसार ही बोलूंगा । महोदय पंजाब समस्या जो है इसने पूरे देश के लोगों के मन को लगातार कई वर्षों से खलीफमय बनाकर रखा है और मैं सोचता हूं कि विस्तारपूर्वक दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने बोलने का काम किया । जो बातें लोगों ने रखी है मैं कोशिश करूंगा कि उन पर ज्यादा न बोलूं । अपने मन में और अपने जेहन में जो ठीक और दुरुस्त बात लगती है वह आपके सामने मैं रखना चाहता हूं । जो मेरे मित्र हैं आज जो राज में बैठे हुए हैं वे पंजाब के सवाल पर ही हैं यानी मैं मानता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की जो घृणित हत्या हुई वह कभी होनी नहीं चाहिए, किसी भी लोकशाही और लोकतंत्र में हत्या से और गोली से कोई काम नहीं बनता, लेकिन यह पंजाब का सवाल ही पूरी तरह से आपने इस सवाल को बिगाड़ करके अपनी तबीयत से चला करके या सुधार के इस सवाल पर ही आप यहां राज में बैठे हुए हैं । मैं इसलिए इसको याद दिलाना चाहता हूं कि पंजाब के सवालों पर, और पंजाब के सवाल को हल करने के लिए यानी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है जो आपने बताया था । जो पिछला चुनाव था उसमें सब से ज्यादा खतरा लोगों के दिमाग में लगता था कि पंजाब का है । उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, देशभर सदमे में डूबा हुआ था । इस सवाल को अपने एकता का सवाल बना करके चुनाव लड़ने का काम किया और चुनाव जीतने का काम किया । मैं सोचता हूं कि चुनाव जीतने और श्रीमती इंदिरा गांधी से पहले भी एक नहीं कई उपाय आप कर चुके है यानी कानून के, लोकशाही और लोकतंत्र को खत्म करने के कई तरह के गवर्नर बदलने के, और मेरे ख्याल से आपने कई गवर्नर बदल डाले । मैं उनके नाम नहीं लूंगा नहीं तो एक लंबी लिस्ट हो जाएगी लेकिन आपने लगातार गवर्नर बदले, लगातार कानून बदले आपने लगातार कई तरह के उपाय पंजाब के सवाल को हल करने के लिए किए ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री मुस्तफाबिन कासिम) पीठासीन हुए]

मान्यवर, ऐसा लगता है कि यह सरकार लोकतंत्र और लोकशाही के जितने उपाय हैं उनसे थक चुकी है और थक करके इसने सारे के सारे उपाय निदान और सारे के सारे रास्ते रबर के रास्ते में देख लिए है । एक पुलिस के अफसर ने देख लिये हैं । हिन्दुस्तान का मानस एक दिन का खड़ा हुआ नहीं है सदियों का खड़ा हुआ है । बहुत से माननीय सदस्य इसे खड़े हुए दिमाग से बोल रहे थे । मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता । यह देश एक वर्ष का, दो वर्ष का, नहीं । लम्बे समय इस देश की गुलामी की है । दुनिया का कोई हमलावर ऐसा नहीं है जो कि कभी इस देश में हार कर गया हो हमेशा जीतकर ही गया है । यदि हमारे संस्कार, धर्म और संस्कृति के साथ समन्वित रूप में महान होता तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारा इतिहास इस तरह का कलंकित नहीं होता, वह इतना दरिद्र नहीं होता ? यह इतिहास हमारा इतना दरिद्र है, हमारे संस्कार इतने बिगड़े हुए है । दुनिया में कोई मुल्क है, जो धर्म के आधार पर बंटा हो ।

जो मित्र कह रहे हैं कि दुनिया में कोई अतिवाद सफल नहीं होता । मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई देश हमारे देश जैसा नहीं है, कोई इंसान हमारे यहां के इंसानों जैसा नहीं है । जितनी बीमार इस देश की कौम है और इस देश का आदमी है उतना

बीमार दुनिया में कम आदमी हैं । यहां इस देश में ऐसे आदमी हैं, 500—700 लोग देवराला में हैं और जब सती होनी वाली लड़की उठकर के भागने लगी तो वहां एक मेरे बहुत पक्के साथी हैं, कहा—आग की लपट से और जलन से जब वह लड़की भागने लगी तो वहां जो डंडा लेकर तड़पन करता है, उसने सिर में मारकर उसे धक्का देकर उस औरत को वहां गिराया, 500 आदमी वहां खड़े थे, उनका विश्वास था कि यह सती विश्वास से नहीं हो रही है, जबरदस्ती लकड़ी मार कर सती की जा रही है, लेकिन कहीं कुछ प्रतिरोध नहीं । यह देश सड़ा रहे, और सड़े तरके से लोगों को मारने का काम चले, यह दुनिया की किसी आबादी में होड़ नहीं सकता । सौ साल, सवा सौ साल का परिवर्तन, समाज परिवर्तन हम एक मिनिट में पी जाते हैं ।

इधर आप टी० वी० पर रामायण सीरियल दिखा रहे हैं, जिसमें रावण के भाई की पत्नी की शहादत और सती होने का बड़ा भारी किस्सा है और दूसरी तरफ सती प्रथा को हमगाली देने का काम कर रहे हैं । हमारे जैसा दूहरा, तिहरा, चौहरा मानस और किसी का नहीं हो सकता । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संस्कार खराब हैं । धन के नाम पर दुनिया में कोई देश बंटा नहीं, यह देश बंटा है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से साफ-साफ कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने और मेरे ख्याल से सन् 1947 की जो तारीख है और आजादी की जो लड़ाई है, उसका सबसे बड़ा नेता है महात्मा जी—महात्मा गांधी । उससे शानदार आदमी इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ । इस देश को शहरी आजादी और इस देश के साधारण आदमी को चाहे वह किसी वर्ग का है, चाहे तांगे वाला है खेत वाला है, चाहे झाड़ू वाला है और चाहे बहुत पूंजी वाला है, सबको बराबर करके जो वोट का अधिकार दिया है, लोकशाही दी है, वही इस देश की सबसे बड़ी आशा है, वही इस देश का सबसे बड़ा विश्वास और सबसे बड़ा सपना है, जिसके चलते यह देश और मुल्क बदल सकता है । यह तभी बदल सकता है, जब उस पर अमल हो । इस देश का आदमी जब चुनाव लड़ता है तब ईमान होता है और चुनाव लड़ने के बाद वह फिर जाति होता है, धर्म होता है, मजहब होता है ।

मान्यवर, मैं एक घटना बताना चाहता हूं । राम का रथ चल रहा था तो उस समय मैं मुजफ्फरपुर में, बिहार के एक टाऊन में था । वहां चुनाव होने वाला था नगरपालिका का । इधर रथ आने वाला था । तो सारी की सारी पार्टियों के लोग आए और बोले कि किसी तरह से इस रथ-यात्रा को रुकवाय, हिन्दू भी मुसलमान भी । तो मैंने कहा—क्यों रुकवाना चाहिए ? उन्होंने सारा एक्सप्लेनेशन दिया, सारी चर्चा की, बहस की और उसका नतीजा यह था कि यदि यह रथ आएगा तो जो चुनाव है, उसमें हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी जीतने में, इसलिए उसको रोका जाय । चुनाव आ गया है, इसलिए रथ नहीं आना चाहिए और यदि चुनाव नहीं होता तो जरूर रथ आना चाहिए । यह मानस है हमारा । जब चुनाव आता है तो सब धर्म के लोग सब तरह के लोग मन में विश्वास करेंगे कि यह देश इस तरह चलेगा, और उनको कहना पड़ता है कि हम सेकुलर है ।

मान्यवर, इस हाउस में इस सदन में और उस सदन में, जो सबसे बड़ा चुना हुआ सदन है, कोई नहीं कह सकता कि धर्म से और संप्रदाय से कोई समस्या हल हो सकती है । यह महात्मा जी का कहा है यह उनका त्याग है, उनके साथ जो पैदा हुए उनके त्याग और तपस्या का फल है ।

मान्यवर, मैं इस राष्ट्रपति शासन की छह महीने की जो अवधि पंजाब में बढ़ाई जा रही है । उसका विरोध करने के लिए अपनी पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं । मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि इस देश की समस्या का समाधान अगर आप चाहते हैं तो साल पांच साल के चुनाव को कुछ और कम कर दीजिए, यदि आप चुस्त रहना चाहते हैं, दुरुस्त रहना चाहते हैं । मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि आप ही खराब लोग हैं, हो सकता है कि हमारी तरफ के लोग उधर बैठ तो इस तरह के

[श्री शरद यादव]

बददिमाग और बद, काम करने वाले हों। मैं मानता हूं कि संस्कार हजारों वर्ष के हैं और उम्र है लोकतंत्र की पांच साल दस साल या बीस साल। हमारे संस्कार हम पर कई बार, कई तरह से, कई जगह से हमला करते रहते हैं। नतीजा होता है कि हम खराब काम में जल्दी लगते हैं, खराब काम की तरफ पूरे देश को ले जाते हैं।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि पंजाब की समस्या का जैसे कुछ यह सरकारी लोग कहते हैं कि वहां पर सरकार बन ही नहीं सकती, जिस तरह से यह इस देश में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब यह है कि सदियों तक आप कांग्रेस पार्टी को घूरा और कूड़ा बनाकर उसमें कीड़े पैदा करते रहिए, यह आपका तरीका चलता है। यही पंजाब में हो रहा है। महात्मा गांधी जी के जमाने में आजादी की लड़ाई में भी ब्रिटिश कहते थे कि यह देश आप से नहीं चल सकता है, इसको आप काबू नहीं कर सकते हो। महात्मा जी कहते थे कि इस देश को हम चलाएंगे चले ही लड़ते रहेंगे लेकिन आप अंग्रेज तो चले जाओ। मैं फिर कहता हूं कि वह तर्क कोई तर्क नहीं है। राजीव गांधी की सरकार पूरी तरह बदनाम हो चुकी है। यह सरकार जिन वायदों पर बनी है, उसमें मुख्य मुद्दा पंजाब का था। लोग भूल गए। मानस छोटा होता है हम लोग भी इतने मजबूत नहीं हैं कि अगर वायदाखिलाफी की तो गर्दन पकड़कर आपको बाहर फैंक दें। लेकिन देश फैंक रहा है। इसलिए मैं आप सब से कहना चाहता हूं कि यदि आप चुनाव कराएंगे तो ही पंजाब की समस्या का समाधान निकलेगा। वहां आपने प्रदेश के दो हिस्से कर दिए हैं। एक हिस्से में भारतीय रहेगा और दूसरे हिस्से में... वहां अगर एक आदमी भी राष्ट्रभक्त है तो हमें उसके लिए कानून बनाकर रखना पड़ेगा। यदि ये आपका मानस है कि सब अकाली खालिस्तानी ह तो यह देश को बांटने का तरीका है, हिटलर का तरीका है। देश की आजादी की लड़ाई में सिखों और अकालियों का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। इस देश में जब इमरजेंसी लगी तो इस देश में सब जगह सन्नाटा था। लेकिन स्वर्ण मंदिर से अकालियों ने, सैंकड़ों लोगों ने गिरफ्तारी दी। उन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस देश में यदि 5 वर्ष के बजाय 2 वर्ष में चुनाव कराए जाएं तो समस्या का समाधान जल्दी होगा। इस देश में जब कमजोर सरकार रही है, तो कार्य अच्छे हुए हैं। जिस समय सन् 71 में श्रीमती इंदिरा गांधी जीती थीं या मध्यावधि चुनाव हुआ था, मान्यवर जो पुराने लोग बैठे हुए हैं वे जानते हैं कि जब इंदिरा जी कमजोर थीं तभी उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था, तभी राजाओं के प्रिवीपर्स बंद किए गए थे। मान्यवर, यहां जब चुनाव आते हैं, तभी इंसान जागता है और तभी सरकार जनता की तरफ मुड़ती है। इसलिए पंजाब में चनाव करना एक मात्र रास्ता है। आप इस प्रेसिडेंट रूल में 6 महीने में समस्या पर काबू नहीं पा सके। मैं इस सरकार से दो-तीन सवाल पूछता हूं—6 महीने के बाद की आपकी क्या (योजना) प्लानिंग है। आपकी सरकार इसी मुद्दे पर बनी थी और इस मुद्दे का समाधान आपसे नहीं हो रहा है। आप देश में राष्ट्रीय एकता के सवाल पर चुनाव जीते थे। आपको फिर से चुनाव के लिए जनता के सामने जाना चाहिए। तभी इस समस्या का समाधान निकल सकता है। यदि आप बेशर्म बनकर डटे रहें जब तक कि आपकी गर्दन को पकड़कर बाहर न निकाला जाये तो बैठे रहिए बेशर्म बनकर, जरूर बैठे रहिए लेकिन एक उपाय करिए कि ग्राम पंचायतों के चुनाव करवा दीजिए। वहां जो शहर की नगरपालिका है, उनके चुनाव करवा दीजिए। वहां चुनाव प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए। छह महीने के बाद फिर आपको मौका मिला है कि आप पूरे प्रांत में चुनाव करा सकें और मान लीजिए कि आप चुनाव नहीं करा रहे हैं तो 6 महीने

के बाद आपकी क्या जना है? अकेले रेबरो और वहां की पुलिस पर आप कब तक निर्भर रहेंगे । आपने उन्हें वहां भगवान बनाकर खड़ा कर दिया है । आपने यह सोच लिया है कि पुलिस या रेबरो से ज्यादा न्याय करने वाला और कोई दूसरा नहीं हो सकता । आप इस बात पर पहुंच गए हैं । यदि यह आपके अंदर है तो आपका बहुत बुरा अंत होगा। इसलिए आप गांव को पंचायतों के चुनाव करा दीजिए । नगरपालिका के चुनाव करा दीजिए, जिला परिषद के चुनाव करा दीजिए । चुनाव प्रक्रिया, शहरी आजादी की प्रक्रिया को, मत स्थगित करिये वरना यह देश आपको धक्कियाकर निकाल देगा । इस देश में धार्मिक उन्माद की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस उन्माद को मत बढ़ाइए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, पंजाब की समस्या पर यह सदन कई सालों से चर्चा करता आ रहा है । कठिन समस्या है और उस समस्या के निदान के लिए सरकार की तरफ से जो सुझाव आ रहे हैं वे काम नहीं कर रहे हैं । कभी हम राष्ट्रपति शासन बनाते हैं, वह भी काम नहीं कर पाता । आपने फिर राष्ट्रपति शासन कायम किया और फिर कह रहे हैं कि इसको आप बढ़ा दीजिए । यह कोई समस्या का निदान नहीं लग रहा है ।

महोदय, मैंने मंत्री महोदय की रिपोर्ट और जो वक्तव्य उन्होंने दिया उसको ध्यान से सुना । मुझे ऐसा लगा कि किसी मंत्री का नहीं, इंस्पेक्टर आफ पुलिस जैसे वह रिपोर्ट दे रहा है क्योंकि उसमें सिर्फ इतना ही जिक्र है कि पहले इतने मारे जाते थे, अब इतने मारे जाते हैं, पहले इतने पकड़े गए थे, अब इतने पकड़े गए हैं, पहले इतनी छीना-झपटी हुई थीं अब इतनी हुई हैं । हमने उम्मीद की थी कि सरकार के मंत्री की यह रिपोर्ट होगी जिससे पंजाब समस्या के बारे में हम गंभीरता से विचार करें । हमारे सरकारी पक्ष के लोगों ने भी कहा है कि यह राष्ट्रीय समस्या है । ठीक है राष्ट्रीय समस्या है तो उसका निदान भी राष्ट्रीय होना चाहिए । निदान के लिए हम लोग छोटे-छोटे सुझाव देते हैं, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, तो फिर यह समस्या राष्ट्रीय कैसे हुई ? आप कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं । जोधपुर में लोग नजरबंद हैं । हमने कभी यह नहीं कहा कि सबको आप छोड़ दीजिए, लेकिन विचार तो कीजिए । हमने ऐसे ऐसे विचार किया और इतनों को छोड़ा, कुछ तो आप कहिए । आप इस बात पर भी विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं । हमने आपसे फिर यह भी कहा था कि दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में जो सिख विरोधी दंगे हुए उन लोगों को सजा देनी चाहिए, कमीशन ने जांच करके दी है, तो आप इसको भी टालते जा रहे हैं । तो इससे और भी जख्म गहरा होता चला जा रहा है । यह तो साफ है कि या तो आप नालायक हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं । अगर नालायक हैं तो आपके लिए 6 महीने और बढ़ाना हम लोगों की नालायकी होगी । तो जो छोटे-छोटे सुझाव हम देते हैं, उनको भी आप नहीं मानते हैं तो आप कैसे कहते हैं कि यह राष्ट्रीय समस्या है ?

अभी जिस ढंग से बहस चली है और पहले भी सरकार का खयाल था कि इसका एक मात्र हल पुलिस ऐक्शन है और विपक्ष के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसका एकमात्र उपाय राजनीतिक समाधान है । मेरा खयाल है कि आपको दोनों को कंबाइन करना होगा और दोनों में भारत सरकार फेल कर रही है । मैं प्रशासनिक चीज को लेता हूं । आप बार्डर पर पेटी लगाइए सुरक्षा की या नहीं, लेकिन पेट्रोलिंग तो इतनी ऐफिशियेंट होनी चाहिए कि उधर से लोग आ न सकें और हमारे देश में खुराफात न कर सकें । अगर आप यह नहीं रोक सकते हैं तो आप किस मुंह से कहते हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन बढ़ा दो, आप किस मर्ज की दवा हैं? दूसरे, हम कहेंगे कि अभी जो एक नया हथकंडा टैरोरिस्टों ने शुरू किया है वह मोटरेबल रोड्स के एरिया

[श्री चतुरानन मिश्र]

में नहीं, नान-मोटरेबल रोड्स के एरिया मे है वहां वे मोटर बाइक पर आते हैं और कई गांवों मे हत्या करके भाग जाते हैं । आप इसका भी निदान नही निकाल पाएं तो आप वहां पर किस बात के लिए है ?

तीसरी बात, सरकार आतंकवादियों की होने वाली कार्रवाईयों का पहले से अन्दाज कर प्रतिरक्षात्मक कार्रवाई नहीं करती है बल्कि 500-700 आदमियों के मारे जाने के बाद कदम उठाती है । पक्की सड़कों को छोड़ वे गांवों की कच्ची सड़को पर अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, यह सरकार नहीं सोच सकी ।

चौथी बात यह है कि आपकी सैक्युरिटी फोर्स तो बी०आई०पी० लोगो के यहां लगी हुई है और हम लोग जो लड़ने के लिए तैयार हैं, कम्युनिस्ट है या आपकी पार्टी के भी कुछ लोग हैं, मैं नही कहता कि हमारी ही पार्टी के लोग हैं, उनको हथियार देने की बात छोड़िये, यहां पर बूटा सिंह जी नही हैं, हमारी पार्टी के कुछ लोग सिंगापुर मे हथियार खरीदकर ला रहे थे, पर दिल्ली में आकर उनको रोक दिया । जायज खरीदे हुए हथियार भी उनको आज अभी तक नहीं दिए हैं । लेकिन जो आतंकवादी हैं उनको यह खुली छूट है कि वे विदेशों से रुपया भी लेकर यहां बांटें, हथियार भी बांटें । हम रुपया देकर खरीदकर हथियार लाते है तो भी आप हमारी बात को नहीं मानते हैं । यही तो आपकी सरकार चल रही है इसलिए आप को नही रहना चाहिए ।

आप एक-एक गांव को ले लीजिए वे सब थाना हेडक्वार्टर से 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर हैं ये एरिया कौन से हैं ? ये एरिया वे है जैसे मनोचल जहां घनघोर आतंकवाद छाया हुआ है । वहां पर लोगों को थाना में जाने के लिए 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जाकर खबर देनी पड़ती है । तरनतारण में भी ऐसे एक गांव थाने से 20 किलोमीटर दूर है, अमृतसर थाने में भी ऐसे गांव हैं जो 16 किलोमीटर दूर है । इस समस्या का निदान कैसे होगा ? क्या आप इतनी पुलिस दे सकते है जितने वहां पाकिस्तान है ? आपने बी०आई०पी० लोगों को पुलिस दी हुई है और बाकी को मरने के लिए छोड़ दिया है । इसलिए कहता हू कि गांवो में जो विश्वसनीय लोग है जो आतंकवाद से लड़ना चाहते है उनकी सूची बना कर उनको हथियार दीजिए ताकि वे मुकाबला कर सके । आप यह करते नहीं है । नतीजा यह हो रहा है कि लोग मरते जा रहे है और यहा आप डिबेट कर रहे हैं । अभी जगदेवकलां में 12 व्यक्ति मारे गये थे क्योंकि वहां कोई पैट्रलिंग नही थी । इसीलिए मै आपसे कह रहा हू कि आप लोग प्रशासनिक ढंग में टोटली फेल्योर है ।

दूसरी पोलिटिकल साइड है । अकाली दल दो हिस्सो में बंट गया है । दोनों हिस्सों मे टकराव हो गया है । दोनों हिस्से अलग-अलग हो गये है । मै मानता हू इन लोगों ने पहले आतंकवादियों को प्रोत्साहन दिया था । मै यह भी मानता हू कि भिंडरवाला को रूलिंग पार्टी ने प्रोत्साहन दिया था । आपने उनको सत कहा था । इस देश में राजनीति ऐसे ही चल रही है । देशद्रोही कौन है इसे माप हम अपने वोट के लिए राज चलाने के लिए कर रहे है । आपने भी ऐसा काम किया था, अकाली भी करते थे । अभी कुछ नई बातें आयी है कि नेशनल कंसेंसस होना चाहिए । लेकिन अगर पार्टी के सदस्यगण तो इंस्पेक्टर आफ पुलिस के निर्णय के समर्थन में आप लोग हाथ उठाने के लिए तैयार हैं । जब ऐसा है तो हम लोगों की क्या जरूरत है । (व्यवधान) यहां से तो वाक-आउट कर सकते हैं लेकिन पंजाब से तो हम वाक-आउट नहीं कर सकते । सदन से हम वाक-आउट कर सकते हैं । इसी लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं ।

अभी अकाली दल के दोनों दल आतंकवादियों के खिलाफ हो गये हैं । एक गुट के नेता बादल और टोहरा जेल में हैं । हम कहना चाहेंगे कि आप इनको एक बार छोड़ दीजिए और फिर देखिये

वह क्या बोलना चाहते हैं । पहले जैसा बोलते हैं तो फिर जल भेज दीजिए, आतंकवाद का समर्थन करते हैं तो फिर उनको जेल भेज दीजिए । अभी जो उनमें मतभेद उठा है उसका भी आपको फायदा उठाना चाहिए और उसके बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए । जो श्रीगुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी है उनसे भी आतंकवादियों का टकराव हो गया है । आप इसके बारे में विचार कीजिए और कहिये कि हम ऐसा कर रहे हैं । लौंगोवाल के साथ जो समझौता हुआ था उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है । आपकी सरकार अब हरियाणा में नहीं है । हरियाणा में दूसरी पार्टी की सरकार है । पहले जब आपकी सरकार थी तब आप कोई सैटलमेंट नहीं करा सके । अब नई सरकार आयी है उसके साथ विचार करना होगा । उसको जनता ने चुना है । अगर आप उसके भी खिलाफ होंगे तो वहां पर भी आन्दोलन शुरू हो जायेगा । मैं आप से कहना चाहता हूं कि बरनाला जी के वक्त में एक काम अच्छा हुआ था । वे सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग जो आतंकवादियों से लड़ना चाहते थे उनको मिलाकर आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चलाना चाहते थे । जब से आपका शासन आया है यानी राष्ट्रपति शासन आपने उस कार्रवाई को ठप्प कर दिया, बंद कर दिया । अब आपकी पार्टी अकेली खड़ी है । सभी पार्टियां अलग अलग काम कर रही हैं । (सवा पांच बजे) मैं यह कह रहा था कि नये एलीमेंट पंजाब की राजनीतिक में आ गये हैं । इसलिए प्रधान मंत्री जी अविलम्ब सभी राजनीतिक पार्टियों को जो रिकोगनाइज्ड पालिटिकल पार्टीज हैं, के साथ बैठकर इस पर बातचीत कीजिए और इस मामले का निदान कीजिए । अलग अलग बात करके और फिर सामूहिक ढंग से बात करके कोई रास्ता निकालें । समस्या की जड़ अभी भी धर्मान्धता है, इसको आप मत भूल जाये । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और अभी हमारे पूर्व वक्ता जो हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रामायण दिखाया जा रहा है इसके द्वारा धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं । कांग्रेस के लोगों ने भी इसका विरोध किया है । इसलिये आपको इस सवाल पर गहराई के साथ विचार करना चाहिए । मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं । जो वर्तमान सरकार है वह मजदूर विरोधी रुख ले रही है । मजदूर लोग बराबर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं । हमारे दर्जनों मजदूर मारे गये हैं । फिर भी अभी सरकार ने मिनिमम वेज जो रिवाइज्ड किया उसमें ईंट-भट्टा मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, एग्रीकल्चर वर्कर्स, पी० डब्लू० डी० के मजदूरों की तनख्वायें को रिवाइज्ड नहीं किया है क्योंकि आप सामतों को खुश करना चाहते हैं इसलिये आप खेत मजदूरो की तनख्वाह नहीं बढ़ाना चाहते हैं । जो आपकी मदद में हैं, जो आतंकवाद के साथ मुकाबला करने में आपकी मदद करते हैं उनके पक्ष में आप काम नहीं करते हैं और फ्यूडल एलीमेन्ट्स के साथ गठबंधन करते हैं । अभी 65 दिनों तक नर्सेज की हड़ताल हुई लेकिन आपने उसको भी नहीं सुना । इसलिये राष्ट्रपति शासन मजदूर विरोधी शासन के रूप में काम कर रहा है । इसलिये हम कहेंगे कि आप इसकी अवधि मत बढ़ाइये ।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, शासक पार्टी के बहुत से लोग आजादी की लड़ाई में लड़े हैं और वे जानते हैं कि पुलिस क्या है । इसको वे समझते हैं । कल शासक पार्टी के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हरियाणा में बूथ कैप्चरिंग हुई है । इससे हमको लगा कि अब वे समझने लगे हैं और अगर थोड़े दिनों में और भी विपक्ष की सरकारें ज्यादा राज्यों में कायम हो जांय तो तब इस बात को और ज्यादा समझने लगेंगे । अभी थोड़ी कसर है । जब तक बिहार और उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सरकार नहीं आ जाती है तब तक शासक पार्टी के लोग सारी बात नहीं समझ सकते हैं । . . . (व्यवधान) . . . आप पुलिस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं । मुझे रैबरो के बारे में कुछ नहीं कहना है । लेकिन जैसी हमारी पुलिस है उसके बारे में हम सब जानते हैं । वहां भी इसी तरह के लोग पुलिस हैं वे कहीं और से नहीं आये हैं । हम को

[श्री चतुरानन मिश्र]

आप बतायें कि क्या फिर वहां गांधी जी ने जन्म लिया है और वे वहां पुलिस आफिसर हैं, क्या इंदिरा जी ने जन्म लिया है ? वही पुलिस वहां भी है जो यहां है। महोदय, मैं एक घटना का उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी पुलिस कैसी है। महोदय, दरभंगा जिले में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर वहां कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जनता पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां की पुलिस ने उन नेताओं को पकड़ कर और किस कोटि के नेता लोगों को जो कि तीन-तीन बार एम० पी० रह चुके हैं श्री भोगेन्द्र झा, श्री विजयकांत, ठाकुर डिस्ट्रिक्ट सैक्रेटरी सी०पी०आई० एम०), श्री शिव चरण सिंह जो कि जनता पार्टी के सैक्रेटरी हैं उनको बुरी तरह घायल कर दिया। उनको हैड इंजुरी है और वे आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज में हैं। वहां तो आतंकवाद नहीं था। देश में बेशक आपको राज चलाने का हक है। लेकिन जो प्रजातंत्रीय ढंग से लड़ना चाहते हैं और किसी समस्या का निदान निकालना चाहते हैं तो उनके साथ आपका इस तरह का व्यवहार क्या उचित है ? इसीलिये आज देश में टेरोरिज्म डेवलप कर रहा है, लोग उधर जा रहे हैं। जिस तरह से दरभंगा की घटना हुई अगर ऐसी ही घटनायें होती रहेंगी तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं स्वतंत्रता सेनानी हूं, मैं भी लोगों से कहूंगा कि आप हथियार उठा लें क्योंकि यह सरकार बिना हथियारों के सुनने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति आप देश में पैदा कर रहे हैं। आज पंजाब की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है। इसलिये मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि सभी विपक्षी लोगों के साथ बैठकर बात की जाये और वहां की राजनीति में जो नये एलीमेंन्टस आ गये हैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया आप इसका समाधान निकालिये। नहीं तो 6 महीने क्या, ऐसे कितने 6 महीने हम देंगे और केवल पंजाब ही नहीं, एक दिन ऐसी स्थिति आ जायेगी जब कि सारे भारत में प्रेसीडेंसियल सरकार की आवश्यकता आपको महसूस होगी, ऐसी आपकी दिशा जा रही है। इसलिये इसको आप रोकिये और इस प्रजातंत्र को, इस रिपब्लिक को बरबाद मत कीजिये। कहीं ऐसा न हो कि काले अक्षरों में आपका नाम लिखा जाये। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Mr. Vice-Chairman, I rise to oppose the adoption of the resolution for extending the Prresident's rule in Punjab. President's rule in Punjab in the last six months has brought nothing but misery, greater alienation of the Sikhs from the mainstream, greater schism between the two communities and given greater fillip—and I would like to stress this point—to the concept of Khalistan than ever before. With the collapse of the democratic processes and with the resign of terror and corruption let loose by the unpopular and incompetent Punjab Government, there is much greater aversion, bitterness and even disgust against the Central authority. Firm belief has taken root that the Centre is only interested in destroying the very fibre and clan of Sikh communty which was proud of its glorious role in the service of the country, both before and after independence.

In the last six months there has been a veritable reign of terror and a shooting match between the police forces on one side and militants of various shades and hues on the other. It has given an opportunity to the anti-social elements of both sides to play havoc with the innocent and well-meaning people of the Punjab. While smugglers, dacoits, drug traffickers and gunrunners have continued to loot and kill for self-aggrandizement, the corrupt elements in the police forces are busy in harassing the innocent to extract money and improve their chances of promotion by killing innocent persons in false and fake encounters. Ribeiro himself has admit-

ted publicly that his police is corrupt as everywhere else and he had to sack 50 people for extracting money from poor parents to get the release of innocent young people. Further, some of the senior officers, while denying that they kill innocent people in false encounters, have admitted that they had killed such militants against whom they have proof that these people had killed more than five persons. Now, who is the arbitrator to decide whether these people have killed five persons or not? The police themselves. Unless a person is found guilty, he is innocent. That aspect has been totally forgotten and the new black laws have made it possible for the corrupt police force to further play havoc with the innocent people. Myopic and blatantly autocratic attitude of the powers that be in the Centre has shown little or no sensitivity or imagination to take advantage of certain helpful and hopeful signs to strat the process of political dialogue, to understand and solve the problem during the last six months. Deliberately or foolishly every effort has been made to discredit and destroy the moderate leadership thereby strengthening the hands and credibility of the militants and divisive forces. All constructive efforts by Akal Takht Jathedar Prof. Darshan Singh have been blatantly sabotaged to justify the contrived excuse by this Government that there is no one to talk to.

It is a point of greater interest that while talking to Baba Amte, the DG of Police, Mr. Ribeiro, in Punjab in the last week of September, stated that he was satisfied with the results. There were only 60 to 70 hard-core terrorists left, it would take him 9 to 10 months to liquidate them, after that it would be possible to contain the present movement but at no stage can it be eliminated. That means terrorism in Punjab. He and quite a few of his senior police officers who had met Baba Amte gave their assessment that their efforts could only make a ten per cent contribution towards solving this problem while ninety per cent is in the hands of the Government. They felt that the only possible positive political step was to assuage the hurt Sikh psyche and only that will improve the climate, when certain political measures can be taken.

Mr. Ribeiro himself has said that he felt that releasing the Jodhpur detenus would be one step in the right direction.

Now, Sir, I do not want to go into the figures of those killed during the last six months as these figures have been given by the various people. But, if Mr. Ribeiro in spite of this feels that he is achieving something, then we must give him credit for being a great optimist. But even if his confidence is well-founded, he at no stage claims that terrorism can be completely eradicated by police measures nor does he feel that his efforts are likely to contribute heavily towards finding a lasting solution. How then is the Government expending all its energies and resources in killing and jailing such a large number of people many of whom may be innocent? I feel that if the aim is to create the peace of the dead, maybe the present method, as decided by the Government at the Centre, can succeeded, but only temporarily. If the aim is to create a climate of peace, amity and mutual confidence, you have failed miserably and you have caused tremendous damage to the Punjabi spirit. As distance in this vast country goes, there is not much physical distance between Delhi and Amritsar. But the emotional distance, however, puts Amritsar in a different planet. For the sake of ten per cent you may be winning the battle of the bullet. But you are well on your way of losing the battle of the mind which is ninety per cent of the problem. The victory in the battle of the bullet can only be transitory and may well become the cause for losing the war. You cannot bind people by force, by chains and shackles. You can, how-

[Sardar Jagjit Singh Aurora]

ever, bind them strongly and firmly with super glue of trust, mutual understanding and credibility.

If the Central Government has any plans and is sincere in its intentions to solve the Punjab problem, it should spell out how it intends to use the next six months to restore and re-establish the democratic process, how it intends to re-establish its credibility amongst the people and win their confidence, how it intends to create a feeling of belonging as opposed to oppressive dominance, how it is going to meet the justifiable demands which, even though once accepted, remain totally unfulfilled, when it is going to start respecting human rights and human values and set free those people who have been incarcerated for so many years, how it is going to remove the false image... (*Time bell rings*)...created by its own media and, above all, how it is going to establish the rule of law.

Let the people breathe breath of real freedom. When is it going to punish the guilty of the heinous crimes of November 1984 killings? If the Government has a plan, an honest plan, and honest intentions to implement the above-mentioned requirements, there may be some justification to extend the President's rule for the next six months. But from the past records of the last six months, and of the previous period of President's rule in 1984-85, one can have little hope and faith in the present Government about either the intention or the ability or the competence to do any of the things suggested earlier.

Under the circumstances, I do sincerely feel that a further extension will only cause greater misery to the people of Punjab and an irreparable damage ot the democratic foundation and solidarity of the country.

Thank you.

SHRI DARBARA SINGH (Punjab): Sir, I will be brief. I have not heard the earlier speakers because I was away, outside the country Therefore, I will confine myself to what I have to say. पंजाब की प्राबलम हम जब देखते हैं तो एक पक्ष से ली जाती है वह यह कि इसको एक्सटेंड न किया जाए ।

मैं उस बात में नहीं पड़ना चाहता जो दिपार्टिड मीटिंग में सारी पार्टियां मिल कर आकाली दल को मजबूत करने के लिए और उसका फैसला करवाने के लिए उनके हक में क्या-क्या बातें उन्होंने कही हैं, मैं उसमें अब नहीं जाऊंगा क्योंकि वह बहुत बिटर बातें हैं जिन्होंने यह सिचुएशन डेवलप की । अब उनको कभी-कभी यह ख्याल आए कि हमने गलत बात की है, उस वक्त अकाली पार्टी की सपोर्ट इस हद तक करके—कि जो केस था उसको असली तौर पर नहीं समझा, बल्कि उनकी एक बिलकुल इस ढंग से मदद की आंख को बन्द करके, अब मैं उस बात को खोलूं, तो जरा तलख बात है, लेकिन मैं जरा आज की सिचुएशन अर्ज करना चाहता हूं ।

यहां बहुत कुछ कहा गया कि वह यह खराबी है, वह खराबी है, करप्शन हो रही है । मुझे यह नहीं पता कि बरनाले की सपोर्ट बहुत हुई, भलामानस होगा, ठीक होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, मैं तो यह कहता हूं कि इनके वक्त में एक पेरेलल गवर्नमेंट बनी और वह वह थी टेरोरिस्ट की। उनका जो मिनिस्टर पकड़ा गया, उससे लाखों रुपया गवर्नमेंट ने निकाला है। करप्शन की इंतहा थी उस वक्त और लूट बाजार गर्म था । इसलिए इस सब चीज को लगाना पड़ा कि यह बात चलेगी नहीं क्योंकि उनकी एंट्री, टैरोरिस्ट के अपने सिम्पेथाइजर्ज की एंट्री उस वक्त हुई जब वह सरकार थी और उन्होंने ऐसे आदमियों को दाखिल किया हर शोब में, हर गवर्नमेंट के काम में, जो लोग उनके साथ थे, उनकी सिम्पेथी करते थ और वह

टैरोरिज्म को ज्यादा हवा देने के लिए उनका मुआवन बन रहे थे, ताकत बन रहे थे। अब अगर उसको कंटिन्यू आज तक करते, तो आज सारे के सारे पंजाब में आग लगी हुई होती।

रेबीरो को कुछ कहें, ठीक है कि कुछ आदमी गंदे थे, पुलिस में--उन्होंने उनको काबू किया है और काफी हत्तक की बात होती है वहां कि बाहर से आदमी आया है, लेकिन वह इस ढंग से चल रहे हैं कि उन्होंने कंट्रोल किया है। आज देहात में हो, कस्बात में हो, किसी जगह हो, एक कानफिडेंस आया है कि कोई ताकत है सरकार की जो इन टैरोरिस्ट्स को मीट करती है और इस सिचुएशन को काबू में करने में सफल है। यह कानफिडेंस अब अवाम में आया है। लोग अब भी मर रहे हैं, यह और भी शायद चले। लेकिन यह कानफिडेंस लोगों में जरूर आया है, बावजूद इस बात के कि वहां किलिंग्ज हैं। यह कहां से आया है? यह पुलिस के टाइटन करने से, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करने के लिए रेबोरो ने जो कुछ किया है--ही इज ए ब्रेव मैन, वी मस्ट एप्रिशिएट, उन्होंने जो कुछ किया है। अब वहां निहायत एक्सपीरिएंस्ड पालिटिशन जो था, अब वह गवर्नर बन गया है। उन्होंने कहा है कि अब मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। ठीक बात है गवर्नर के तौर पर वह काम करते हैं... (व्यवधान) आप में से बहुत से डिफीट होकर फिर आ जाते हैं, क्या करें। लेकिन सवाल यह कि वह लोग अब डिफीटड कितने हैं, हम भी डिफीट हुए हैं और आप भी कितनी बार डिफीट हुए है। आप यह बात छोड़िए। राजनीति में किसी की जिन्दगी हमेशा के लिए पायेदार नहीं है। वह ऊपर-नीचे होती रहती है। आप कभी नीचे गए, कभी आगे आए और हम भी कभी नीचे गए और कभी आगे आये। प्राइम मिनिस्टर को आपने 1977 में हमें सब को चलता कर दिया और हमने आपको 1980 में चलता कर दिया। ... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : अब फिर चलता होने वाले हैं।

श्री बरबारा सिंह : शायद आपको हम चलायें। हमें विश्वास है कि आपको हम चलायेंगे। आप भी जरा बाहर की सैर ज्यादा करें बनिस्बत अन्दर के, आप यह बात छोड़िए कि क्या होने वाला है। हम तो इस बात के हक में हैं कि गरीबों को भी उसके हक में सब कुछ हो। आप भी चाहते हैं और करेंगे तथा उस बात के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मैं आज पंजाब के बारे में कहना चाहता हूं। यह कहना कि सैन्टर ठीक बात नहीं करता, उसका मन ठीक नहीं है, इंटेंशन ठीक नहीं है, मैं कहता हूं कि अगर इंटेंशन ठीक नहीं होती तो आज जो हालत है वह भी न होती और उससे भी खराब होती। पिछले साल ठीक है मर्डर्ज हुए हैं, किलिंग्ज हुई हैं लेकिन यह कहना कि यह हिन्दस्तान की सरकार की वजह से हुई हैं मैं समझता हूं कि इसमें कोई जान नहीं है। इसमें कोई तर्क नहीं है, लौजिक नहीं है। कहते हैं कि इन्नोसैंट्स को मारा जा रहा है उन्होंने लिस्ट मांगी है कि दीजिए, कौन से निर्दोष आदमी हैं जो कि मारे गए हैं। आजतक तो किसी ने दी नहीं। यह कहे जाना और प्रोपेगंडा के तौर पर मीडिया को इस्तेमाल किया जाना यह अलग बात है, वह आप कर सकते हैं क्योंकि यहां पर किसी को इजाजत है। यहां डेमोक्रेसी है और यह इस हद तक चली गई है कि राइट्स को हम लेते हैं, हमने रेसपांबिलिटी का कभी ध्यान नहीं किया। यही बात हमारे खिलाफ जा रही है। कि राइट्स के लिए हर कोई अपना सर उभारता है लेकिन रेसपांसिबिलिटी को डिसचार्ज करने के लिए उनकी कोई हिम्मत और सोच नहीं है। आज कहते हैं कि करप्शन है। जरूर होगी। लेकिन हम दूर करने की कोशिश करते हैं। हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है और सरकार चल रही है। पिछले 6 महीने में वारदात की बात नहीं करता,

[श्री दरबारा सिंह]

लोगों में कंफीडेंस जरूर आया है। आज मैं यह जरूर कहता हूं कि आप किसी देहात में चले जाइये, हिन्दू और सिख का आपस में कोई कलेश नहीं हैं। कलेश किस बात से है, वह यह है कि कभी किसी ने यहां नाम लिया कि पाकिस्तान की दुकानें वहां खुली हुई हैं, वहां से वे असला लेते हैं और ट्रेनिंग देकर यहां भेजते रहे हैं और अभी भी स्नीकिंग हो रही है, कभी काश्मीर की तरफ से हो जाए, कभी राजस्थान की तरफ से, कभी नेपाल की तरफ से हो जाए। कहीं न कहीं से असला लेकर आयेंगे। मारने-मराने की बात अभी तक जारी है। अब वे रन पर हैं। कभी दिल्ली में छुपते हैं और कभी इधर-उधर जाते हैं, 100 के करीब होंगे जो लोग बिल्कुल डाई हार्ड डाई टैरोरिस्ट्स हैं। उनको काबू करने के लिए कहते हैं उनके बारे में कहते हैं कि वे इन्नोसेंट हैं। अगर वे इन्नोसेंट हैं तो दुनिया में किसको इनोसेंट आप कहेंगे जो लोगों को भरे बाजार में आकर मारते हैं, उनको कत्ल करते हैं और भाग जाते हैं। अगर उनको कहीं पकड़कर मार दिया जाता है एनकाउंटर में तो कहते हैं कि इन्नोसेंट को मारा जा रहा है। यहां दो पार्टियों की बात कही गई अकाली दल आपस में लड़ा, मुझे यह पता नहीं लगा कि गुरुद्वारे का इस्तेमाल क्यों इस बात के लिए किया जाता है पोलिटीकल बात के लिए आनंदपुर साहब में दोनों इकट्ठे हुए, एक ऊपर मीटिंग कर रहा है एक नीचे कर रहा है। वह उनको गाली दे रहा है, वह उनको गाली दे रहा है। वह कहता है कि मेरे साथ ज्यादा हैं, वह कहता है कि मेरे साथ ज्यादा हैं। अब किसके ज्यादा हैं और किसके ज्यादा नहीं हैं इसका पता नहीं चलता। एक बात कभी किसी ने नहीं कही कि हम इकट्ठे होकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे, वी विल कम विद द हैड एंड टेल आफ् इट। किसी ने कहा है? केवल बातें करने से काम नहीं बनता। केवल किसी का लिखा लिखाया पढ़ने से कोई बात नहीं बनती। बात तब बनती है जब आपको उसका पूरे तौर पर ज्ञान हो, अगर स्थिति का पूरी तरह से विश्लेषण करें। अगर वे आपस में लड़ते हैं अगर जो आदमी जेल में हैं इनके लीडर्ज उन्होंने नहीं किया और जब पिछली बार प्रेसीडेंट चुने गये गुरचरण सिंह टोहरा जी चुने गए उन्होंने तीसरे दिन जो सेक्योरिटी के अन्दर आदमी रखे हुए थे उन सब को कहा कि बाहर निकलो, तो फौरन कब्जा किसका हुआ? टैरोरिस्ट्स का कब्जा हुआ। यह झंडा जो खालिस्तान का लहराते हैं इधर-उधर जाकर उसके पीछे यह है कि तमाम जो शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी थी उन्होंने अपने आपको वहां से विदड्रा कर लिया। अब खाली जगह देख कर कोई भी ऊपर कर ले। इसलिए उन्होंने कभी किसी को नहीं जाने दिया। आज गुरुद्वारे में जाने से लोग एतराज करते हैं, नहीं जाना चाहते, न सिख चाहता है और न हिन्दू चाहता है। कहते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमें पीस आफ माइण्ड नहीं मिलेगा, वहां से डिस्टर्बेन्स मिलेंगी क्योंकि वहां वह लोग हैं, जिनके बारे में क्या आपने अखबारों में नहीं पढ़ा कि गुरुद्वारे में कितने क्रेक्टर के खिलाफ बातें हुई हैं। अखबारों में जो निकला है, उसका किसी ने जवाब भी नहीं दिया है। गुरुद्वारे के अंदर जो कमरे रखे हुए हैं अन्डरग्राउन्ड हैं, उसके बारे में अखबारों में आया है, लड़कियों को दिखाया, उन्होंने लेडीज को दिखाया, विडोज को दिखाया, जिनको दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी इस बात का ख्याल रखा है, किसी ने कंडम किया है, जो अपने आपको अकाली कहते हैं या अकालियों के नुमायंदे कहते हैं। आज वह भी दो हिस्सों में चला गया है। कभी बरनाला जी स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर बना लो, कभी दूसरी पार्टी स्टेटमेंट देती है कि मुझे चीफ मिनिस्टर बना लो। चीफ मिनिस्टरी के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन टेरोरिज्म का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि पाकिस्तान के साथ दोस्ती है। इनके साथ पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, पैसा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, आदमी भेज रहा

है, प्लानिंग कर रहा है, साथ ही कहता है, कि ट्रेनिंग जो है हमसे लेकर आओ और यह काम करो। डिस्टेब्लाइजेशन अगर आप इस तरह से करते हैं, पंजाब में सब कुछ हो रहा है, आप गलतफहमी में हैं, पंजाब में जो सिचुएशन पैदा की जा रही है यह टेरोरिस्ट ने की है, उसमें यह बात सारे हिन्दुस्तान से ताल्लुक रखती है . . .

Once destabilisation starts from that area, the whole of the country will be involved in it. We must understand that people have taken to killing to start such movements in the *rest of* India. *You do not* know what is going on. These killings are going on with a purpose and it is being done there also.

तो आप इसलिए उसको यह न समझिए कि पंजाब की समस्या जो है गाली-गलौज निकालने से हल हो जायेगी। एडमिनिस्ट्रेटिवली वे कर रहे हैं। हां, एक बात मैं मानता हूं कि जो लोग इनोसेन्ट है, कहीं भेजे हुए हैं उनको वापस कर दिया जाये। लेकिन जिन्होंने दस-दस कतल किए हुए हैं और लोगों को पता है, बाहर आने के लिए या गवाही देने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोर्ट में जाने से पहले मेरी छाती पर गोली होगी टेररिस्ट की, लेकिन मारे हैं उन्होंने यह सबको पता है, अगर आप उनका कहते हैं कि उनको छोड़ देना चाहिए तो आप टेररिज्म को इन्क्रीज करना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि जो इनोसेन्ट हैं, उन को वापस करना चाहिए।

ठीक है, हम भी सोचते हैं कि पेकेज प्रोग्राम गवर्नमेंट का होना चाहिए, जिसमें कि सारी चीज हो, उसको जो इकनोमिकली नुकसान पहुंचा है, उसके लिए भी हो और यह ड्राउट में भी कोई काम किया है, आप जाकर देखिए जो बोनस मिला है किसान को, उससे किसानों में इस बात की खुशी है कि हमें बोनस मिला है, जो खराबी हुई है, उसका बदला मिला है। इस तरह से बहुत कुछ हुआ है। उसके साथ-साथ डिस्ट्रिब्यूशन जो है, वह इक्वीटेबल हुई है। आपने कभी देखा है यह हिन्दुस्तान में।

महोदय, मैं देखता हूं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, 1925 का जो एक्ट है, उसके मुताबिक बना हुआ है। आप यह बताइए, कांस्टीट्यूशन में यह प्रोवीजन है कि नहीं कि हम रिलीजियन को प्रोटेक्शन करते हैं, उसको प्रमोशन नहीं देंगे क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट का, जो भी सत्ता में आए, उसका रिलीजियन कोई नहीं है। जो एक डिस्क्रिमनेटरी पहले की हुई है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कांस्टीट्यूशन में दिया है, उसके मुताबिक हमें चाहिए कि हमारा हिन्दू, हरिजन या क्रिश्चियन या किसी भी और रिलीजियन के लोग जो हैं, उनके लिए कोई एक्ट ऐसा नहीं बना हुआ, जिसमें गवर्नमेंट आप खुद अपने चुनाव कराएं और चुनाव कराने के बाद उन लोगों के हाथों में दे दे जो रिलीजियन और पोलिटिक्स को इकट्ठा मिलाकर हमारे खिलाफ सारे हिन्दुस्तान में एक विवाद पैदा करे। यह होता रहा है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि रिलीजियन और पोलिटिक्स को अलहदा-अलहदा करने की बात करनी पड़ेगी और जो भी देश में कम्युनल पार्टी है उसके साथ हमें अपना रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर यह बात हो सकती है।

अगर आप निश्चित कर दें कि जो अकाली पार्टी जो रिलीजियन और पोलिटिक्स को इकटठा करके चलती है वह अलहदा-अलहदा कर दे यानी जो रिलीजियन में काम करने वाले हैं, वह रिलीजियन में काम करें, वह ग्रंथी बनें या कोई और चीज बनें तो बन जायें, लेकिन उनको यह कभी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वह पोलिटिक्स में आएं और इसी तरह जो पोलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं वह गुद्वारे में न जायें अगर आप ऐसा कोई लेजिसलेशन यहां भी पास कर दें, तो भी ठीक है। मैं तो इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं और

[श्री दरबारा सिंह]

कांग्रेस पार्टी की पालिसी भी यह है कि जो कम्युनल पार्टी है, उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो यह बातें करने को हैं। अगर उसके लिए आप हमारे साथ मिलकर चलें और इस गवर्नमेंट को हम कहें कि ऐसा लेजिस्लेशन लाना चाहिए कि पालिटिक्स और रिलीजन को अलहदा कर दें तो इस तरह आपकी आधी से ज्यादा प्राब्लम दूर हो जाएगी। आप यह क्यों नहीं कहते कि यह एक रीजन है जो हमें वहां मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ हम देखें कि 6 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट की यह कोशिश होगी कि वहां नार्मलसी आए, उसका जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वह आए। लेकिन उसके लिए हालात पैदा करने की जरूरत है। यहां हमारे एक दोस्त शर्मा जी ने कहा कि वहां सब पार्टियां इकट्ठी हुई हैं—अकालियों के वक्त हुई हैं या उसके बाद हुई हैं। यह गलत बात है। अगर पार्टी इकट्ठी हुई है तो उन्होंने गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के कंडेमिनेशन के कुछ नहीं किया है। लेकिन उसका क्या फायदा है। हम कांग्रेसवाले आज वहां लगे हैं। हम इकट्ठे चलने के लिए तैयार हैं। जो कम्युनल पार्टी नहीं है, वह हमारे साथ आए। हम इकट्ठे चलने के लिए तैयार है। आज किसी ने आने को इस बात के लिए कंफाइन नहीं किया है कि टेरोरिज्म कैसे खत्म हो सकता है? अलहिदा-अलहिदा गाली-गलौच करते हैं। उसके आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। यह पार्टी का सवाल नहीं है, यह हिन्दुस्तान का सवाल है। पंजाब में टेरोरिज्म का मुकाबला करने का सवाल है। इसके लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं।

इसके साथ हम कहते हैं कि इकोनोमिक प्रोग्राम वहां होने चाहिए। यूथ को इक्वालब करना चाहिए। लाखों लोगों को इक्वालब करना चाहिए। कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह नहीं कहा कि हम इसे हल नहीं करना चाहते। लेकिन जब तक टेरोरिज्म हमारे सामने है, हम किसी फिरकापरस्त से बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो टेरोरिज्म को हवा दें और हम उनसे बात करें तो यह दो बातें कैसे हो सकती हैं। पहले वहां नार्मल हालात होने चाहिए। वहां अकाली दल दो हिस्सों में बंटा हुआ है। ये दोनों कहें कि हम टेरोरिज्म से लड़ने के लिए तैयार हैं। यह एक आदमी भी नहीं कहता। यहां किसी ने सिर नहीं उठाया कि बिलकुल गलत बात हो रही है। वहां करप्शन है। इस के लिए एक हद तक गाली-गलौच दी जा सकती है। मैं तो यह कहता हूं, प्रोफेसर दर्शन सिंह का नाम लिया गया, हमने कब कहा कि वे गुरुद्वारा में न जाएं। लेकिन वे डरते हैं। पता है जाने से पहले ही परमात्मा की तरफ रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, इसलिए नहीं जाते। हमने कब कहा कि वे पैर पड़कर अपना फैसला न करवा लें। दर्शन सिंह समझदार आदमी हैं। वह काम करने लगे थे तो कहा गया कि यह हिन्दू सरकार से मिला हुआ है। किस बात के लिए वह यहां आए हैं। वे आए नहीं। कोई संदेश भी नहीं आया। वे आपस में यह कहते हैं। उन्होंने यह रेजोल्यूशन पास तो कर दिया कि आनंदपुर साहिब का जो रेजोल्यूशन है, वह बड़ा खतरनाक रेजोल्यूशन है। अलहदगी की पालिसी उसमें मौजूद है। हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। आनंदपुर साहिब मानी हुई जगह है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके नाम पर हिन्दुस्तान को तोड़ने की कोशिश की जाय। इसलिए integrity of the country depends on this that we go to villages and make the people feel that we are with them and the whole of India is with them.

उनकी मदद कीजिए। आइए इकट्ठे होकर चलें। एडमिनिस्ट्रेटिवली वे काम कर रहे हैं और पोलिटिकली हम काम करें ताकि पंजाब फिर आगे बढ़ सके और पंजाब फिर अपने पांव पर खड़ा हो सके। इसके लिए जरूरी है कि आज जो काम चल रहा है उसके लिए और वक्त इस सरकार को मिल सके ताकि 6 महीने के अन्दर हम इस हद तक पहुंच सकें कि

वहां नार्मलसी की स्थिति आ जाय और हमारे आसपास किसी प्रकार का खतरा न रहे कि पाकिस्तान टेररिस्ट्स को ट्रेन्ड करके हमारे यहां भेज रहा है और टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI T. R. BALU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, once again, this Government is closing the doors of democracy as it seeks the permission of Parliament to extend the President's Rule under article 356 of the Constitution. Sir, time and again, article 356 has been described by many democrats as the Sword of Damocles which hangs just above the heads of State Governments. This article has often been described as a dangerous weapon in the hands of the Central Government.

[The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai) in the Chair.]

Sir, this Resolution is an ample proof that the Punjab accord has miserably failed like the other accords which the Prime Minister entered into. What is happening is daily bloodshed as we see in Sri Lanka where the Indian Army is waging a war employing 30,000 troops, hundreds of tanks and aircraft under the guise of disarming the militants. This Government is only deceiving us and the people. I do not agree that by extending the President's Rule, we will be able to bring about an improvement in the law and order situation in Punjab. I would like to point out in this connection that after Punjab came under President's Rule six months ago, the number of killings has increased and it is higher than was the case under Barnala's Government. Therefore, no useful purpose is going to be served by extending the President's Rule.

I would like to ask the treasury benches, what happened to the democratically-elected popular Government? Why are you keeping the Assembly in suspended animation? What about the Jodhpur detenus? Either you should release them or you should initiate legal proceedings against them. You are not doing either. You are continuing to keep them in prison. You are continuing to detain Mr. Tohra, who is an hon. Member of this House, as well as Mr. Badal. Thousands of innocent people are still behind bars. I have my own doubts whether the Government of India will be able to bring about peace in Punjab by extending the President's Rule. Therefore, I urge upon this Government to desist from this path and restore to power the democratically-elected Government. I would also request that the Jodhpur detenus should be let off. Mr. Tohra, Mr. Badal and other innocent people should also be released. The democratically-elected Government should be given a chance again to rule the State which will be in a better position to bring about normalcy. I would ask this Government not to bring forward such Resolutions in future. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Chitta Basu. You are known for your brevity of speeches, by asking pointed questions. I hope you will do so this time also.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Sir, it is a great pleasure for me to speak in this House when I see you occupying the Chair. You, sometimes, are a source of inspiration to me and since you have odered me to be brief, I will be brief today also as I have always been.

Sir, I rise to oppose this Statutory Resolution which seeks to extend the tenure of President's Rule in Punjab. There are various reasons and grounds on the basis of which I oppose this Statutory Resolution.

First of all, it is admitted even by the Ministry and the Government that the situation has not improved to the extent as was desired or

[Shri Chitta Basu]

expected by the Government itself while imposing the President's rule. As a matter o ffact, the situation has further worsened and if some Members on this side want to contest me on this statement, Sir, I have got all the figures at my disposal to show that the situation, instead of improving, has further worsened and worsened at a very rapid pace. Therefore, in order to be brief, for the sake of brevity I do not wish to take resort to those figures which have been given by many Members of this House and which have been supplied by the Government itself.

Now, I am very much in disagreement with the approach of the Government regarding Punjab and its Punjab Policy. That is the main reason of my opposing this extension. As a matter of fact, Punjab problem is a very deep, social, human and political problem. My grouse against the Government is, the Government right from the beginning has refused to accept this very essential character of the Punjab problem. Again I repeat it is a deep social, human and political problem and this is not confined to the geographical limits of Punjab only. I am in agreement with Mr. Darbara Singh, who was just now saying from that side of the House that it is not only the problem of Punjab, it is the problem of the nation as a whole because of the destabilisation programme of the foreign enemies is going to succeed in this country, it may succeed first in Punjab and then it will ultimately spread all over the country. Therefore, it is a national problem. It is a national problem, it is a political problem and my opposition to the Government's Punjab policy is based on this fact. The Government has, conviently or for reasons of their own which they have never explained to this House or to the countrymen, refused to accept it as a political, national problem of this great republic.

Now I do not minimise or rather do not rule out that there is no aspect of law and order. I do not rule it out completely. Mr. Vice-Chairman, you should not misunderstand me, nor the House nor the countrymen should misunderstand me, but the quintessence of the problem is political. Law and order problem is, of course, there, but that is subsidy. That is not the cause, that is the result, that is the consequence. Therefore, law and order dimension has been acquired subsequently. But as situation has developed in Punjab, both political and law and order should be so wisely combined that the situation can be tackled and a desired result is obtained. I want a mixture of the two approaches. But unfortunately, again I rise to accuse the Government that they have not accepted that position also because I find in certain utterances, policy utterances of the Government, that they are more interested in having the primacy of law and order aspect, denying or ignoring the political aspect of the problem. In order to prove or substantiate my allegation against the Government, I want to quote the Prime Minister himself. The Prime Minister said in a television interview last week that terrorism was the job for the police and the army and "once the task is completed, we will talk to people and take steps to introduce a lasting political solution". This is a wrong assessment of the situation. I altogether disagree that terrorism is the job for the police and the army. What can I do? It comes from the highest authority in our country—the Prime Minister—that terrorism is to be fought by army and police. Government is wrong in that respect. Here I would say that to fight terrorism, politics is also needed. Without politics, without commitment, without motivation, you cannot fight another motivated force, whatever wrong ideology, or whatever misleading, confusing ideology they may ascribe to.

Again I come to our great Home Minister of the Republic, Mr. Buta Singh. He is on record to say that no political solution can be sought till the

back of terrorism is broken. What can I do? Unfortunately I do not agree with this kind of statement. I not only do not agree with this kind of statement, but I also feel that it is a wrong approach, it is a suicidal approach. I do not want to use any other adjective or epithet. And that approach is ultimately complicating the issue. Thereby the entire nation is to suffer, unity and integrity of the country is to suffer. I am only concerned over that. I am a patriot and like many of you I feel that this approach will not lead to the integration of the country, but will lead ultimately to disintegration, and for this you, the ruling party, will be responsible.

Even the police officers are wiser than them. When our Prime Minister, when our Home Minister Buta Singh says that there is nothing political in fighting terrorism, they say that even to wipe out terrorism, some political instruments are needed. I find somebody saying that police officers in Punjab admit that forty new trrorists are born every time one dreaded terrorist bites the dust. That is, if they kill one terrorist, forty terrorists are created. I think the police officers' assessment is correct in that respect. But the Prime Minister says that there cannot be any political solution and terrorism is the task for the police alone and the army alone to fight.

Sir, I am concluding. The Government and the Home Minister might have taken note of the significant changes which have of late taken place in the Punjab scenario. Much of the facts have already been mentioned here by Shri Chaturanan Mishra who preceded me. There have been some changes in the political scenario in Punjab following from the contest on the question of leadership of SGPC and the stance taken, of late, by Prof. Darshan Singh Raagi. New popular forces are also coming up who desire for peace. That desire for peace has to be converted into a struggle for peace. And for that some political motivation is needed. Unfortunately, under the Presidents rule, that process which was initiated by the Barnala Government by way of organizing, initiating, an all-party campaign for national unity and integrity leading to the delinking of politics from religion, was discontinued by your Governor.

Therefore, to conclude, I think the Government should have a re-assessment of the whole situation, revise their stanse, seek a political solution of the problem and work out a programme by which larger and larger sections of the people of Punjab can be involved in the campaign for unity. The divide between the Hindus and Sikhs in Punjab is not to be allowed to be widened—it has to be narrowed —and it should be followed by certain economic programmes also.

Lastly, I suggest that the Government should initiate an all-party meeting in order to evolve such a political programmes so that greater and greater sections of the people can be involved in a wide mobilization for

national unity and integrity, which alone can save Punjab, save the country, save the nation save the Republic and the Constitution of our country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shri Satya Prakash Malaviya. Five minutes. Please cooperate with me today. You are always cooperating.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उपसभाध्यक्ष जी, जब पंजाब के चुनाव के नतीजे आए थे और उसके बाद जब अकाली दल बहुमत में आया तो हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि पंजाब क चुनाव में भारत की जीत हुई है और 11 मई, 1987 को उसी भारत की जीत के फलस्वरूप जब पंजाब में बहुमत की सरकार थी जो अल्पमत में नहीं थी यह बिलकुल निश्चित था कि उसका बहुमत था उस सरकार को असंवैधानिक ढंग से इस केन्द्र की सरकार ने बर्खास्त कर दिया उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था । पिछल अगस्त के माह में जब इसी सदन में चर्चा हुई थी तो राष्ट्रपति शासन का हमने विरोध किया था । मेरी ऐसी धारणा है कि जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई जिस पार्टी के अध्यक्ष श्री राजीव गांधी हैं तो पिछल दरवाजे से सत्ता हथियाने की वहां पर कोशिश की गई और उसका फल था विधि द्वारा निर्वाचित बहुमत की सरकार को बर्खास्त करना और राज्यपाल को वहां पर बैठाना और राज्यपाल भी ऐसा जिनका सीधे-सीधे सम्बन्ध उस दिन तक कांग्रेस पार्टी से था और पिछले लोक सभा के चुनाव में बंगाल में उनकी पराजय हो गई थी 1981 से ले कर 1987 के बीच में श्री राय वहां के आठवें राज्यपाल थे । मेरा ऐसा मत है कि जो पंजाब समस्या है यह सही है कि यह देश की समस्या है, लोकतन्त्र की समस्या है लेकिन इसका समाधान राष्ट्रपति शासन द्वारा नहीं किया जा सकता है । इसलिए मैं अपनी मांग को दोहराता हूं कि जिस दल का वहां पर बहुमत हो राज्यपाल उस दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाएं और उनको सरकार चलाने का मौका दिया जाना चाहिये । मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि 12 मई, 1987 से ले कर 31 अक्तूबर तक 446 नागरिक मारे गये, 197 आतंकवादियों की हत्याएं हुई, 49 पुलिस के लोग मारे गये । मान्यवर, अभी विद्वान सदस्य श्री चित्त बसु प्रधान मंत्री जी के उस वक्तव्य की चर्चा कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पहले आतंकवाद को समाप्त करूंगा, उसके बाद बातचीत का सिलसिला जारी करूंगा । हालांकि इस समस्या का राजनीतिक समाधान है लेकिन उसका मार्ग ढूंढना है । मेरा ऐसा विश्वास है कि पंजाब में आतंकवाद की जो समस्या है और पंजाब की समस्या है यह राजनीतिक समस्या है तथा दोनों का समाधान साथ-साथ ढूंढना चाहिये क्योंकि आतंकवाद इस देश में पिछले 10 साल से चल रहा है । आखिर

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

भिंडरावाले को किसने बढ़ाया, किस पार्टी के लोगों ने बढ़ाया इस संबंध में मैं साप्ताहिक "दिनमान" के 24 से 30 जून, 1984 के बीच में इसी सदन के सदस्य ले० जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के साक्षात्कार को पढ़ना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जब संवाददाताओं ने उनसे पूछा तो माननीय अरोड़ा जी ने कहा कि "भिंडरावाले को बनाने वाला कौन था ? यही कांग्रेसी ना। क्या कभी उन्होंने भिंडरावाले का नाम लेकर उनके कार्यों की भर्त्सना की थी ? यहां तक कि जब मैं एक बार आकाशवाणी पर कुछ बोल रहा था तो मुझसे खास तौर पर ताकीद की गयी कि मैं भिंडरावाले की भर्त्सना न करके आतंकवादियों की निंदा करूं। आप ही तय करें कि दोषी कौन है ?" और इसी भिंडरावाले के लिए किसने बतलाया था कि भिंडरावाले की कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षा नहीं है बल्कि भिंडरावाले एक संत हैं, एक साधू हैं। लेकिन मान्यवर, फिर भी जब यह समझौता हुआ 24 जुलाई, 85 को, हालांकि उसकी कुछ धाराएं हरियाणा के हितों के विरुद्ध थीं जिसका हम लोगों ने विरोध किया था किन्तु इस समझौते में श्री राजीव गांधी और सरदार हरचरण सिंह लोंगोवाल जी जो शरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष थे, ने कुछ आकांक्षाएं व्यक्ति की थी और हम लोगों ने समझा था कि भले ही समझौते की कुछ धाराएं ठीक नहीं हैं लेकिन हो सकता है कि देश के हित में हों, देश की एकता और अखंडता के हित में हों और पंजाब के समझौते में उनको हासिल कर सकें इसलिए हम लोगों ने संतोष किया था। मान्यवर, क्या इन लोगों ने इच्छा व्यक्त की थी : पंजाब समझौते में लिखा हुआ है :—

"This settlement brings to an end a period of confrontation and ushers in an era of amity, goodwill and cooperation, which will promote and strengthen the unity and integrity of India."

24 जुलाई, 85 को यह समझौता हुआ। सवा दो साल के करीब हो चुका है और मजबूर होकर सिद्धार्थ शंकर रे जो वहां के राज्यपाल हैं उनको कहना पड़ रहा है कि आज पंजाब में बूचड़खाना हो गया है और गाजर मूली की तरह लोग काटे जा रहे हैं। जब यहां पर राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति शासन में लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं तो क्या केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। वहां पर असफलता हुई है जो अक्षमता है इसका जिम्मेदार मैं केन्द्र सरकार को मानता हूं और वहां पर राष्ट्रपति शासन को कायम करके, राज्यपाल के जरिये राज करके इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है।

जोधपुर के सिलसिले में (**समय की घंटी**) इसी सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 3524, 25 अगस्त, 87 में माननीय सदस्य श्री अरोड़ा जी ने प्रश्न पूछा कि जोधपुर की जेल में रखे गये 365 व्यक्तियों के विचारण के संबंध में सरकार क्या क्या विचार कर रही है, जो जून 84 में गिरफ्तार किये गये थे। सवा तीन साल हो चुके हैं लेकिन मान्यवर, अभी तक न्यायालय में जिसको कहते हैं चार्जशीट वह भी अभी तक नहीं दाखिल की गयी हैं। साढ़े तीन साल से ज्यादा हो गये हैं बिना मुकदमा चलाये लोगों को जेल में रखा गया हैं। मान्यवर, जिस समय हमारे देश का संविधान बनाया गया था, मैं नहीं समझता हूं कि संविधान निर्माताओं की यह इच्छा थी या संविधान निर्माताओं की यह अपेक्षा थी कि हमारे देश में साढ़े तीन साल तक बिना मुकदमा चलाये लोगों को जेल में रखा जाये। मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी किसकी है। अदालत में चार्जशीट भेजने का जिम्मेदारी किसकी है ? इस सरकार की जिम्मेदारी है और अगर सरकार अदालत में जोधपुर के जो बंदी हैं उनके सिलसिले में आरोप-पत्र नहीं भेज पाती है तो यह सरकार की असफलता है और जोधपुर के जो बंदी हैं उनकी रिहाई की मैं मांग करता हूं। उनको छोड़ दिया जाय। मुकदमा फिर चल सकता है। जमानत

पर छोड़ते हैं। मुकदमें में सजा हो जायेगी तो फिर पकड़कर जेल भेजे जा सकते हैं।

इसी तरीके से मान्यवर, प्रकाश सिंह बादल और गुरचरण सिंह तोहड़ा की रिहाई की मांग मैं करता हूं। आखिर उनको जेल के बाहर आने दिया जाये। उनके विचारों को सुनें। किस तरीके से समस्या का समाधान करने में वे सहायक हो सकते हैं इसके बारे में उनको सुनना चाहिए और माननीय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट जब पिछला सत्र चल रहा था तब रखी गयी थी लेकिन अभी तक उस पर विचार नहीं हुआ है। रंगनाथ मिश्रा ने 84 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे जो लोगों का नुकसान हुआ उसके संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं। आज भी मान्यवर, वे लोग अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसलिए मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट के संबंध में सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके लोगों की जानें गई हैं, जिनके प्रतिष्ठान नष्ट हुए हैं, उनको पर्याप्त रूप में मदद देनी चाहिए।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर अपनी मांग को दोहराता हूं कि अगर बरनाला साहब सरकार चलाने में वहां असफल रहे हैं, तो उससे बड़ी दोषी स देश की सरकार है, इस देश की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इस देश के प्रधान मंत्री और जिस बात की ओर मान्यवर शरद यादव जी ने ध्यान दिलाया कि सन् 1984 में श्री राजीव गांधी ने जब देश की जनता से वोट मांगा था, तो उन्होंने यही कहा था कि हम इस देश में शांति कायम करेंगे, इस देश के लोगों को शांतिमय तरीके से रहने का मौका देंगे, लेकिन चूंकि पिछले साढ़े तीन साल से सरकार असफल रही है, तो अच्छा होता कि चूंकि अपने आश्वासनों की पूर्ति नहीं की है सरकार ने, तो इस लोक सभा को भंग करवा करके राजीव गांधी को नये सिरे से चुनाव करवाने चाहिएं।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Sir, the objective of the Resolution moved by the Home Minister is to find a solution and to bring back normalcy to the trouble-ridden State of Punjab. But I want to ask whether the President's rule for the last few months could stop violence in Punjab. Could people there live in a peaceful atmosphere? Rather it is seen that violence has spread in other States as well. Hundreds of innocent people have lost their lives and bitterness has developed among the communities in different States bordering Punjab. I have witnessed the President's rule in Assam. I myself was the victim of the President's rule when I was thrown in jail and thrown in a jungle full of wild beasts. It is a fact.

SHRI DHARNIDHAR BASUMATARI (Assam): It is not at all a fact.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Every single person must condemn terrorisim, but the question is who created terrorism in Punjab? The Sikh community has created a golden history in India by displaying their valour and patriotism on many occasions. Then why a section of the Sikh youths have become terrorists? We firmly feel that dealings of the Government are not mature enough and they are yet to find out the areas and issues. These have hurt the Sikhs most. So, without going into the crux of the problem, if the Government again reimposes the President's rule, it will surely aggravate the situation in a hundred ways

In November 1984 ruthless violence took place in Delhi. Thousands of innocent people were brutally killed. We know every action has reaction and what is inevitable follows. But it is true that all Sikhs are not terrorists. The major section of the Sikh community condemns terrorism. My feeling is that instead of handling this sensitive human problem

[Shrimati Vijoya Chakravarty]

with immaturity, the Central Government should deal with this problem with much greater maturity. It should not deal with this problem as a simple ordinary law and order problem. Thousands of Sikhs have been thrown into jail and many innocent youths have lost their lives. I have witnessed this type of killing in Assam. There was also an order to shoot me at sight during the President's Rule in Assam, but fortunately I have been saved. I might also have been killed in a so-called fighting. By putting a large number of Sikh people in prison, inculding Mr. Tohra, nothing can be achieved. One cannot imprison the spirit of men. If a hundred persons are thrown into jail, thousands will come up with fiery spirit. My point is that by putting Punjab under President's Rule for six months nothing could be achieved. What is important is a political solution in Punjab. Instead of extending the President's rule for another six months, the Government should create an atmosphere of love and sympathy to bring normalcy back to the State. Terrorism must be curbed no doubt, but at the same time legitimate demands of Punjab must not be ignored. Political will and imagination of the Government must be there to hammer out a political solution. Then only law and order can be properly maintained. If it is merely a law and order problem probably President's rule would have been the solution. But we feel that President's rule cannot be merely a solution for Punjab problem. It can be solved through democratic process. For a long time a State cannot be denied of political right and this cannot be a remedy. We totally oppose continuation of President's rule for another six months in Punjab. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Thank you very much.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इससे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सवाल जुड़ा हुआ है। लेकिन मान्यवर, जब कल भी यह विषय आया इस सदन में तो माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित नहीं थे और आज भी जब इतना महत्वपूर्ण विषय आया है तो माननीय गृह मंत्री जी यहां पर क्यों नहीं मौजूद हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि आप आदेश दे सकते हैं सत्ता पार्टी के पार्लियामेंट्री आफेयर्ज मिनिस्टर को कि माननीय गृह मंत्री जी आएं और आकर इसका जवाब दें। मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था दें और गृह मंत्री जी को यहां पर बुलाएं।

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Mr. Vice-Chairman, Sir, Mr. Chidambaram is a capable Minister. He is capable of replying. When there is discussion today—we could understand the Home Minister's difficulty yesterday as he had to be in the Lok Sabha—he should have been present her and should have replied. He should have listened to the debate at least. It is very unfair. This House is treated in such a cavalier manner.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Chidambaram is also in the Ministry of Home Affairs. I think he can reply and there is no necessity of the Home Minister being present here. Mr. Chidambaram, please reply.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have listened with great attention to the debate in this honourable House on the Resolution to continue President's rule in Punjab for another period of six month. The debate has covered familiar ground and, therefore, I will not take the

time of this honourable House to recall the events which led to the imposition of President's rule. Nor will I take too much time to enumerate the events that have taken place in the last six months.

In my opening remarks I highlighted the events of the last six months. While there is cause for some satisfaction on certain front, I candidly admitted that the battle is still on and that we face a very difficult task and in this difficult task, at this point of time, we seek the support of this House and the people of this country.

I also express my confidence that in the months to come there will be changes in Punjab which will help us to find a lasting and permanent solution to the Punjab problem. Sir, numbers alone do not portray the scenario in Punjab, but whatever numbers are available must be used in a manner so that we understand the true situation. I do not know how one reads the numbers. As I read the numbers, it seems to me that the intensity of the battle has increased in the last six months not because the Government did not do anything but because the Government has done something, because the Government has shown the will to fight terrorism. Up to the imposition of President's rule, 73 policemen were killed. In five months 49 policemen have been killed. And why have they been killed? They have been killed because, today, the morale of the Punjab police is much higher than ever before. Today, they are willing to join in the battle against terrorists. They are fighting day and night in order to protect you and me, to protect the integrity of this country, and to protece the unity of this country. I pay homage to the brave policemen of Punjab, who are fighting a battle for the whole country. Sir, in the 19½ months up to the President's Rule, 130 extremists were killed. In the five subsequent months, 197 extremists have been killed. In the 19 1/2 months upto President's Rule, 2784extremists were arrested. In the five subsequent months, 1935 extremists have been arrested. The battle today has reached a totally different plane. In fact, I waited patiently, I listened carefully to find out if any one of the Members of the Opposition including General Aurora, referred to the key changes that have come about in the Punjab situation. Sir, today, in Punjab, apart from the Congress, apart from the other National Parties there are three main forces and let us understand the alignment of these forces. Firstly, of course, there is the Akali Dal (Longowal) Party under Shri Barnala which, whatever General Aurora might say, is increasingly marginalised in the Punjab situation and has increasingly become a weak party. Secondly, you have Professor Darshan Singh Ragi supported by the United Akali Dal and a faction of the SGPC. In the last six months, Professor Darshan Singh Ragi had to withdraw from the Golden Temple. He is unable to face the challenge of the terrorists and of the Panthic Committee. The third, and this is the most important element in the Punjab situation which we have to comprehend, face and fight is the Panthic Committee, and no one from the Opposition was willing to narrate the actions of the Panthic Committee nor confront them nor condemn the actions of the Panthic Committee. The debate has proceeded as though the Panthic Committee did not exist. The debate has proceeded as though the Panthic Committee is irrelevant. In fact, many Members, I am afraid, are either ignorant of the Panthic Committee or unwilling to mention it by name. Let us understand one thing clearly, Sir, beginning from the 26th of January 1986, a qualitative change has come about in the situation in Punjab because of the Panthic Committee which is an usurper of all authority in Punjab today. The Panthic Committee is an agent of imperialism. I will presently tell you the things which the Panthic Committee has done and unless you are willing to face the situation, nothing that you say will have any relevance to what we, as a nation, should be doing in Punjab.

[Shri P. Chidambaram]

Sir, we have evidence that the terrorists are trained abroad. We know that training and indoctrination centres have been set up in a not-so-friendly country. We have been able to identify the location of some such camps. We have taken up the matter but we find that while on the surface, there is a protestation of innocence, the truth is that in these camps, training and indoctrination is given to the terrorists. Sir, terrorism today is mixed up with both smuggling and spying. Terrorism is not motivated by ideology as someone likes to believe. Perhaps, there are one or two highly motivated people who have become terrorists but a number of terrorists are common criminals. Jinda who was arrested in Delhi was a common criminal and let us not raise him, and put him on an ideological pedestal. He has no ideology except to kill, to loot, to burn and to steal. Let us not call these terrorists as ideologists, as fighters for a cause. They are mercenaries, they are killers, they are paid and trained by agents of imperialism. Sir, the story goes back, as I said, to the 26th of January, 1986 when the Panthic Committee was formed. Sir, I want to narrate to you just a few dates and what happened on those dates to bring home to this House and to the people the gravity of the danger that we face. After the Panthic Committee was formed, on 29th April 1986, the Panthic Committee said that its goal was Khalistan. On 26th January 1987 a 'sarbat khalsa' effectively under the control of the Damdami Taksal and the Panthic Committee was held. During the proceedings, Khalistan slogans were raised. A 'Gur Matha' endorsing the declaration of Khalistan made by the Panthic Committee on the 29th April 1986 read out without any objections to it. On 13th June 1987, the Panthic Committee issued a hand-out titled 'An appeal to Sikh High Priests'. It claimed that the Khalistan Government had already been formed with Jasbir Singh, nephew of Bhindranwale as the Jathehdar of Akal Takht Saheb and Shri Mann and Shri Manjit Singh and appealed to the five high-priests including Darshan Singh Ragi not to be guided by what they described as the Hindu imperialist Government. The Panthic Committee's hand-out stated that any dialogue with the Govenment should be only after the release of Jasbir Singh and Mann and others. It also contained a warning that the Sikh community would not spare anyone agreeing to a settlement short of establishment of Khalistan. On 21 June 1987, the Panthic Committee said it was ready to negotiate with the Government of India but on the sole agenda of Khalistan. On 6th August 1987, the Panthic Committee rejected the resolution adopted at the Sikh Convention called by Shri Barnala. It pointed out that the resolution recognised the Indian Constitution. But the Panthic Committee did not recognise the Indian Constitution; nor do the people of the so-called Khalistan owe any allegiance to the Indian Republic. Political leaders were advised to utilise the incomes of the Gurudwaras to purchase weapons for the Sikh youth to enable them to meet the Government offensive. On 22 September 1987, in a press note, the Panthic Committee challenged the resolution passed by the SGPC on 20th September 1987 and asserted that the Panthic Committee had the authority to appoint the high priests. It also warned that anyone appointed by the SGPC would have to spend his life under the protection of the armed guards provided by the Government. On 7th October 1987, in an eleven-page statement, which I think is an open declaration of war against the lawful Government in this country, the Panthic Committee announced the formation of an eleven-member Council of Khalistan with Gurmuk Singh Havlak as President. If you look at the members of this Council, you will find that many of them reside permanently in the United States and in Canada. Two of them described by the Panthic Committee—and I am reading a translation in English—are

Satnam Singh of Dal Khalsa based in Pakistan and Wadwa Singh, Chief Lieutenant of Suk Dev Singh Babbar, also normally based in Pakistan. This is the hand-cut of the Panthic Committee. Here is an organisation which has usurped all authority. It has claimed that it has the authority from the Sarbat Khalsa to decide religious matters, temporal matters and political matters. It claims authority over the Akal Takh and it claims authority over the SGPC. It says that it is the sole authority to decide the future of the Sikhs and it says that it will negotiate on the sole agenda of Khalistan. The Panthic Committee has excommunicated Mr. Badal and Mr. Tohra. And here we are told, "Please negotiate with them'. Whom do we negotiate with? What do we negotiate on? There is no agenda on which you can negotiate with these people. And it is in this context that you must read the Prime Minister's statement, it is in this context that you must read the Home Minister's statement. We are committed to finding a political solution in Punjab. After years of bitter dispute it was Prime Minister Rajiv Gandhi and this Government who reached an accord on Punjab. Eight out of eleven points have been implemented in that accord and there are only three points which have not been ... (*Interruption*) If Gen. Aurora continues to believe in what he has Spoken—I have listened to his speech and I have made notes—then he must stand up and say that he will confront the challenge of the Panthic Committee. You cannot say that. The Panthic Committee has excommunicated your leaders; they are nowhere in the picture...

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: The Panthic Committee has been given importance by you. If you give me a chance, I will prove to you that the Panthic Committee has received importance because you tried to destroy successfully the moderate leadership of Darshan Singh or anybody who could have fought the Panthic Committee. You have sabotaged it.

SHRI P. CHIDAMBARAM: After the announcement by the Panthic Committee of the formation of the Council of Khalistan, if anybody stands up and says, "Negotiate with them", we will be negotiating the unity of India which this Government will never do...

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Who said it? Nobody asked you to negotiate with anybody on the unity and integrity of India. Don't misinterpret it. You are giving a wrong interpretation. You cannot give that interpretation.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: We take no notice of the Panthic Committee. It is the failure of the Government to handle the Panthic Committee.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please sit down. You had your say. Don't interrupt.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Government repeats its resolve, Government repeats its commitment, that we must find a political solution to the problem in Punjab...

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: But when?

SHRI P. CHIDAMBARAM: We have said this repeatedly and I reafirm our resolve and our promise. Many Members have spoken but I would like to quote to them what an eminent CPI leader of Punjab, Mr. Satpal Dang, has written and spoken. The article is very well known; I have quoted it on the previous occasion. Mr. Satpal Dang, who understands Punjab better than anyone of us do, has cautioned the Government, has cautioned the people, against falling into this trap of negotiating with this Panthic Committee. He has categorically said, "Don't appease the terrorists. We have to fight the terrorists and win the minds of the people."....

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Who asked you? Did we ask you

[Shri Parvathaneni Upendra]

to negotiate? Did we use the word 'negotiate? We said, find a political solution. Does it mean 'negotiate with the terrorists'?

SHRI P. CHIDAMBARAM: You were not present here when other Members spoke...

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Nobody suggested that.

SHRI P. CHIDAMBARAM: You have not heard what others have said. You were not present when the debate was on. (Interruptions) There is no point in honourable friends getting excited. I have listened to this debate since yesterday. Let them go through the record and let them show if any honourable Member on the side of the Opposition made a reference to the Panthic Committee and the dangers posed by the Panthic Committee. They are oblivious of the Panthic Committee. They should go through the record. Today it is very easy to say, 'restore popular Government in Punjab'. What is this popular Government? I assume they mean a majority Government. Who has the majority in Punjab? Mr. Barnala appeared to have a majority but he lost that majority in the first few months. Mr. Barnala continued in office only because of the support extended by the Congress-I and the moment we came to the conclusion. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He has only narrated facts... (*Interruptions*). He has only narrated the facts. Why are you agitated on this issue?

श्री शरद यादव: सबसे ज्यादा पापुलर फोर्स हो गई हैं... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please sit down, Yadavji. He has only narrated the facts. Yes, Mr. Minister, you continue.

SHRI P. CHIDAMBARAM: The moment we realised that the Government of Mr. Barnala, however well-motivated and good he might be, had lost the will to fight terrorism and his Government had disintegrated under the weight of its own contradictions, the Congress (I) decided to stand by the people rather than by the Government of Mr. Barnala, and we took on this onerous responsibility. But I said; We do so with trepidation, but with hope; we do so realising the awesome responsibility that we are taking on our shoulders; we do so knowing full well that we are open to criticism; and we do so because we owe a duty to the people of this country, a duty which Mr. Rajiv Gandhi and his Government have been called upon to discharge... (*Interruptions*).

Sir, may I conclude by saying that in the battle against terrorism and separatism, and in winning the minds of the people, we seek the help and co-operation of all sections of society and of all the political parties? I am grateful to those political parties which have mobilised public opinion against terrorism and separatism. Our greatest ally in ths battle is the vitality and patriotism of the great people of Punjab who have refused to let the fear of terrorism disrupt their life pattern and communal amity. The masses of Punjab have always adhared violence. Now some religious and other leaders also have come out against the killings and against separatism and it would be necessary to work assiduously to elicit people's co-operation. The security forces will continue to maintain the maximum pressure on the terrorists.

Sir, I wish to assure the honourable Members that coupled with hard action against the terrorists, the Government will take every possible step to resolve Punjab problem.

Sir, I seek the support of this honourable House to the Resolution which has been moved. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now, I shall put the Resolution to vote.

The question is:

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 11th May, 1987, under artirle 356 of the Constitution, in relation to the Sate of Punjab, for a further period of six months with effect from the 11th November, 1987."

The motion was adopted.

SHORT-DURATION DISCUSSION ON THE INCIDENT OF 'SATI' AT DEORALA IN RAJASTHAN

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Gurudas Das Gupta, you have to start the discussion. ...(*Interruptions*)...All of you please take your seats. We have to start the Short-Duration Discussion...(*Interruptions*)... All of you, please be seated. Yes, Mr. Das Gupta, you please start.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I feel really ashamed...(*Interuptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): All of you, please maintain peace in the House. Yes, Mr. Das Gupta.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I really feel ashamed that I have to raise a discussion on the incident of burning a woman alive in the village, Deorala, in Rajasthan, not very far off from the capital of this country. We have really earned eminence and our eminence is not because...(*Interruptions*) Sir, will you kindly restore some order in the House?...(*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): All of you, please keep silent. Yes, Mr. Das Gupta, you can speak a little bit loudly.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, we have really earned eminence.

[The Vice-Chairman (Shri G. Swaminathan) in the Chair.]

But we have not sent our astronauts into the space nor have we been able to lift the Reliance Cup. But we have earned eminence because a woman in her teens has been burnt alive to death or roasted to death in the village of Deorala in Rajasthan. The singular tragedy, unparalled in the modern century has really shaken the national conscience, has stirred national feelings. And I am constrained to say that it is not the womanhood whose dignity has been outraged but it is really India which been humiliated. The national honour of the country is in peril.

3.00 P.M.

[The Deputy Chairman in the Chair.]

Madam, it is quite consistent at the moment that the House is being presided over by a lady. Let me point out, Madam, that the point before the country is not whether fanaticism shall overtake civilization. The point before the country is whether criminality is going to be condoned under the plea of non-intereference into religious rights. The point is whether militant religious fanaticism is going to be curbed or not. The point is whether male chauvinism will be allowed to usurp the light to burn down their ladies to know whether they are faithful to their husbands. The point is whether the State shall perform its ultimate responsibility of enforcing law and order. The point is whether the State shall perform its duty which is the constitutional responsibility. The point is whether the national leadership shall have the courage to confront the march of fanatic, revivalist, medieval, barbaric and terrorist forces with determination.

Madam, I hang my head in shame there has been an episode of 'Sati' 150 years after it was abolished when Bentinck was the Viceroy of the coun-